सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

"सिर्फ अपनों के होने से कुछ नहीं होता,
उन अपनों में अपनापन का एहसास भी होना चाहिए..!"
अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–90 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, सोमवार 20 अप्रैल 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

वेदांता पावर प्लांट हादसा : मौत का वीडियो सामने, 600 डिग्री की भाप ने ली 24 जिंदगियां

नई दृष्टिबिंदु / सक्ती

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित वेदांता के थर्मल पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे ने अब और खौफनाक रूप ले लिया है। घटना के नए वीडियो सामने आए हैं, जिनमें ब्लास्ट की भयावहता साफ दिख रही है— और उसी के साथ मौत का आंकड़ा बढ़कर 24 पहुंच गया है।

14 अप्रैल की दोपहर करीब 3 बजे सिंघीतराई स्थित प्लांट में बॉयलर का प्रेशर ट्यूब फट गया। इसके बाद जो हुआ, वह किसी औद्योगिक त्रासदी से कम नहीं था। करीब 600 डिग्री सेल्सियस तापमान का खौलता पानी और भाप अचानक पूरे प्लांट एरिया में फैल गई। कुछ ही सेकंड में काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए।

बढ़ रही मौतें, कई की हालत गंभीर

हादसे के बाद से मौतों का सिलसिला थम नहीं

रहा है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज और रायपुर के निजी अस्पतालों में भर्ती कई श्रमिकों की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाज के दौरान लगातार मौतें होने से मृतकों की संख्या 24 तक पहुंच चुकी है, जबकि 11 से अधिक घायल अब भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।

इलाज कई अस्पतालों में जारी

घायलों को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज, बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल और रायपुर के निजी अस्पतालों

में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक कई मरीज 70-80 प्रतिशत तक झुलसे हुए हैं, जिससे खतरा अभी भी टला नहीं है।

एक पल में तबाही, हर तरफ अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाके के बाद प्लांट में भगदड़ मच गई। खौलती भाप और पानी के बीच फंसे मजदूर खुद को बचाने के लिए भागते रहे, लेकिन तापमान इतना ज्यादा था कि बच निकलना आसान नहीं था। कई लोग वहीं गिर पड़े।

सवालों के घेरे में सुरक्षा व्यवस्था

इस हादसे ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इतना बड़ा प्रेशर सिस्टम फेल कैसे हुआ? क्या मेंटेनेंस में लापरवाही हुई? और सबसे अहम—क्या मजदूरों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित थी? यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की बड़ी चूक की ओर इशारा कर रहा है। जांच जारी है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ यह साफ हो रहा है कि यह त्रासदी सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं, बल्कि कई सवालों का विस्फोट भी है।

वीडियो में दिखा 'मौत का गुबार'

सामने आए वीडियो में तेज धमाके के बाद धुएं और भाप का घना गुबार पूरे परिसर को निगलता दिखाई दे रहा है। लोग इधर-उधर भागते नजर आ रहे हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई मजदूर मौके पर ही झुलस गए।

विशेष टिप्पणी

महिला आरक्षण बिल—सियासत का शोर या सच का शिकार?

आलोक तिवारी

'कौआ कान ले गया' वाली कहावत भारतीय राजनीति पर शायद ही कभी इतनी सटीक बैठी हो, जितनी आज महिला आरक्षण बिल के मामले में बैठती दिख रही है। देश में शोर है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण रोक दिया, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और असहज करने वाला है।

सवाल सीधा है—क्या वाकई महिला आरक्षण बिल गिरा, या उसे गिराने की पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी? साल 2023 में संसद ने भारी समर्थन के साथ महिला आरक्षण विधेयक पारित किया। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। यानी कानून बनने का रास्ता साफ था। लेकिन इसके बावजूद इसे लागू करने में देरी क्यों हुई? यही वह पहला सवाल है, जिस पर सत्ता की नीयत कटघरे में खड़ी होती है।

फिर अप्रैल 2026 में अचानक घटनाक्रम तेज होता है। एक तरफ लोकसभा की सीटें 545 से बढ़ाकर 850 करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाया जाता है, दूसरी तरफ उसी अस्तित्व में न आए कानून में संशोधन की तैयारी! यह विरोधाभास ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। सरकार को यह भलीभांति पता था कि संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत चाहिए—जो उसके पास नहीं है। फिर भी बिल लाया गया, बहस हुई, और अंततः वह गिर गया। लेकिन असली खेल यहीं हुआ—जैसे ही यह बिल गिरा, महिला आरक्षण से जुड़े बाकी संशोधन बिल भी चुपचाप वापस ले लिए गए।

यानी निशाना कुछ और था, और शोर कुछ और मचाया

राजनीतिक रूप से देखें तो यह 'नैरेटिव सेटिंग' की क्लासिक रणनीति है—जहां असफलता को विपक्ष की 'विफलता' बनाकर पेश किया जाता है। सत्ता पक्ष अब इसे विपक्ष के महिला विरोधी' रुख के रूप में भुनाएगा, जबकि विपक्ष सरकार की 'नियत' पर सवाल उठाएगा। सच्चाई यह है कि अगर सरकार चाहती, तो साधारण बहुमत से महिला आरक्षण लागू करने के रास्ते खुले थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तब 2029 से पहले ही आरक्षित सीटों पर चुनाव कराना पड़ता—और शायद यही राजनीतिक असहजता असली वजह है।

इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू है—देश का ध्यान असली मुद्दे से हटाकर 'राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप' की ओर मोड़ दिया गया। जनता को लगा कि लड़ाई महिला अधिकारों की है, जबकि असल में यह सत्ता की रणनीति का हिस्सा बन गई। राजनीति में यह नया नहीं है। 90 के दशक से महिला आरक्षण हर बार 'करीब आकर' रुक जाता है। वजह एक ही—जब बात 'अपनी सीट' की आती है, तो सिद्धांत पीछे छूट जाते हैं।

विडंबना देखिए, पंचायतों और नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने में कभी इतनी हिचक नहीं दिखी, क्योंकि वहां टॉप लीडरशिप' की कुर्सी सुरक्षित रहती है। लेकिन संसद और विधानसभा में आते ही समीकरण बदल जाते हैं। अंततः सवाल वही—क्या महिला आरक्षण सच में प्राथमिकता है, या सिर्फ चुनावी मुद्दा? देश की महिलाओं को आरक्षण की जरूरत है या राजनीतिक ईमानदारी की—यह तय करना अब नेताओं के हाथ में नहीं, जनता के हाथ में है। क्योंकि लोकतंत्र में कौए के पीछे भागना आसान है, पर अपना 'कान' बचाए रखना ही असली समझदारी है।

भाजयुमो भिलाई में 'दो सूचियों' का संग्राम

आधिकारिक घोषणा के बाद बगावत, संगठन अनुशासन पर सवाल

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की जिला भिलाई इकाई की घोषणा के साथ ही संगठन के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। प्रदेश स्तर से जारी अधिकृत सूची के कुछ ही समय बाद स्थानीय स्तर पर समानांतर सूची जारी होने से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। मामला अब महज संगठनात्मक मतभेद नहीं, बल्कि अनुशासन बनाम 'व्यक्तिगत वर्चस्व' की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है।

प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार किरण सिंह देव, पवन साय और राहुल योगराज टिकरिहा के मार्गदर्शन में, जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन की सहमति से भाजयुमो जिलाध्यक्ष सौरभ जायसवाल ने जिला पदाधिकारियों, कार्यसमिति सदस्यों, मंडल अध्यक्षों और महामंत्रियों की अधिकृत सूची जारी की थी।

लेकिन इस सूची के जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि भिलाई जिले के कुछ मंडल अध्यक्षों ने प्रदेश से स्वीकृत सूची को नकारते हुए उसी रात अपनी अलग 'टीम' की घोषणा कर दी। यह कदम न सिर्फ संगठनात्मक मर्यादा के विपरीत माना जा रहा है, बल्कि इसे सीधे-सीधे पार्टी अनुशासन की अवहेलना के तौर पर देखा जा रहा है।

अनुशासन पर आंच, छवि पर असर

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं सीधे तौर पर पार्टी की छवि को प्रभावित करती हैं। जिस दल की पहचान मजबूत संगठन और अनुशासन के लिए रही है, वहीं अब दोहरी सूची का विवाद यह संकेत दे रहा है कि जमीनी स्तर पर नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है।

कार्यकर्ताओं में असमंजस

दो अलग-अलग सूचियों के सामने आने से कार्यकर्ताओं के बीच भी भ्रम की स्थिति बन गई है। कौन अधिकृत है और किसके निर्देशों का पालन किया जाए—इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। इससे संगठनात्मक गतिविधियों पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

'संगठन बनाम समूह' की लड़ाई?

स्थानीय स्तर पर जारी समानांतर सूची ने यह संकेत दिया है कि संगठन के भीतर गुटबाजी गहराई तक मौजूद है। जिन नामों को प्रदेश नेतृत्व ने शामिल किया, उन्हें दरकिनार कर अपने 'करीबी' कार्यकर्ताओं को जगह देने की कोशिश ने सवाल खड़े कर दिए हैं—क्या संगठनात्मक प्रक्रिया अब व्यक्तिगत पसंद-नापसंद पर निर्भर हो रही है?

प्रदेश नेतृत्व की परीक्षा

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश नेतृत्व इस 'बगावत' पर क्या रुख अपनाता है। क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी या फिर समझाइश के जरिए मामला शांत किया जाएगा? फिलहाल, भिलाई की राजनीति में यह घटनाक्रम चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यह साफ है कि मामला सिर्फ एक सूची का नहीं, बल्कि संगठन की साख और नियंत्रण क्षमता की परीक्षा का है।

जमानत के बाद घर पहुंचा पति, गुस्से में सिलबट्टे से पत्नी ने कर दी हत्या

पति के खिलाफ लिखवाई थी रिपोर्ट

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

मृतक डोमन साहू

भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र के कैप-2 में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। यह घटना दुर्गा पारा, वार्ड 35 की है, जहां बीती रात पत्नी ने गुस्से में आकर अपने पति पर सिलबट्टे से हमला कर दिया। इस हमले में 40 साल के डोमन साहू की मौके पर ही मौत हो गई।

डोमन साहू और उसकी पत्नी हीरामणी साहू (करीब 35 साल) के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। पड़ोसियों का कहना है कि घर में अक्सर झगड़ा होता था और इसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा था। कई बार आसपास के लोग भी इस विवाद से परेशान हो चुके थे।

मृतक डोमन साहू

पति के खिलाफ एफआईआर

पति-पत्नी के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। मोहल्ले को लोग भी इस बात से परेशान थे। जानकारी के मुताबिक पत्नी हीरामणी साहू ने 19 अप्रैल को अपने पति के खिलाफ जामुल थाना में शिकायत की थी। जिसके बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 170 के तहत उसे गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट भेजा था। कोर्ट से जमानत से छूटा, घर जाकर करने लगा विवाद छावनी पुलिस ने आरोपी पति को एसडीएम कोर्ट में पेश किया। हालांकि वहां से उसे जमानत मिल गई। बताया जा रहा है कि जमानत मिलने के बाद आरोपी शाम को घर पहुंचा और पुलिस में शिकायत करने की बात को लेकर विवाद करने लगा।

पत्नी ने सिलबट्टे से सिर पर किया वार दोनों पति-पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में पत्नी ने अपने पति के सिर पर सिलबट्टे से वार कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना जब पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सुपेला अस्पताल भिजवा दिया। पड़ोसियों का कहना है कि मृतक आए दिन शराब पीकर घर में विवाद करता था और कई बार बच्चों के साथ भी मारपीट करता था। इसी वजह से पत्नी पहले भी परेशान रहती थी और कई बार शिकायत कर चुकी थी।

पत्नी को लिया हिरासत में घटना की सूचना मिलते ही छावनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

करीब 150 मीटर लम्बे सुरंग में अवैध कोयला खनन पर सख्ती, दूसरे दिन भी जारी रहा कार्रवाई

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

कोरिया जिला में अवैध कोयला खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए लगातार दूसरे दिन व्यापक कार्रवाई की। रायपुर से पहुंची सेंट्रल प्लाइंग स्क्वॉड की टीम ने रविवार को देवखोल और भालूमाड़ा क्षेत्रों का निरीक्षण कर अवैध खनन स्थलों का चिन्हांकन किया और उन्हें ब्लास्टिंग कर स्थायी रूप से बंद करने के निर्देश दिए।

इस दौरान जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स, जिसमें खनिज, वन, राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल थे, ने संयुक्त रूप से पूरे क्षेत्र का जायजा लिया। टीम ने बताया कि निरीक्षण के समय मौके पर कोई कोयला या खनन सामग्री नहीं मिली, लेकिन पूर्व में यहां बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थीं। इस कार्रवाई से एक दिन पहले, शनिवार को संयुक्त टीम ने पटना तहसील अंतर्गत देवखोल जंगल में सघन अभियान चलाया था। इस दौरान अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6 टन से अधिक कोयला जब्त किया गया। साथ ही कई अवैध सुरंगों को ध्वस्त किया गया, जिनका उपयोग लंबे समय से कोयला निकालने के लिए किया जा रहा था।

अभियान के दौरान टीम ने करीब 150 लंबी सुरंगों के भीतर प्रवेश कर न केवल कोयला बरामद किया था, बल्कि खनन में उपयोग होने वाले उपकरण जैसे फावड़ा, गेती, विद्युत पंप, फुटबॉल पाइप और बड़ी मात्रा में बिजली के तार भी जब्त किए थे। रविवार को कोरिया के अलावा सूरजपुर, मनेंद्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर और गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिलों के खनिज अधिकारी, स्थानीय पुलिस, वन एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे।

खेल के माध्यम से खिलाड़ी संवार रहे हैं भविष्य– खिलावन सिंह चौहान

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

खिलाड़ियों का भविष्य संवारने का काम अब खेलो इंडिया के खेल में शामिल पेंचक सीलाट मार्शल आर्ट भी कर रहा है। इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों का देश के कई राज्यों में सरकारी नौकरी प्रदान करता है। खेल को कई जगह से मान्यता प्राप्त है छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसके प्रयास किया जा रहे हैं। भारत सरकार खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त पेंचक सिलाट खेल है। इस खेल से आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं।

विषम परिस्थितियों में लड़के हो या लड़की अपने आत्मरक्षा कैसे करेंगे। यह खेल 5 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के खिलाड़ी खेल सकते हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में भी जगह मिलती है इसके अलावा खेलो इंडिया के तहत नगद राशि केंद्र और राज्य सरकार भी प्रदान करती है हर वर्ष देश भर में 30 से अधिक खिलाड़ियों को विभिन्न राज्यों में सरकारी नौकरी मिल चुकी है। इस खेल के माध्यम से आइटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स, असम राइफल्स ,इनकम टैक्स, डाक विभाग, बीएसएफ ,दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस ,उत्तराखंड पुलिस में नौकरियां मिलने की प्रबल संभावनाएं रहती है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान स्थिति में इस खेल का चलन बढा है। राज्य में भी खेलो इंडिया अस्मिता महिला लीग बिलासपुर, दुर्ग, कवर्धा, रायपुर ,बालोद, बेमेतरा ,कोरबा में हो चुका है।

छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी वेस्ट जोन दमन दीव और नेशनल में मेघालय के शिलांग में अपने प्रतिभा दिखा चुके हैं। समुद्र खेल बीच गेम में छत्तीसगढ़ के 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ था जिसमें से एक खिलाड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए कांस्य पदक जीते थे। छत्तीसगढ़ में वर्तमान स्थिति में इस खेल के माध्यम से नौकरी की संभावनाएं तलाशी जारी है, सरकार भी इस पर विचार कर रही है कि खेल के माध्यम से खिलाड़ियों को कैसे नौकरी किस विभाग में दिया जावे। दुर्ग पेंचाक सिलाट एसोसियेशन जिला दुर्ग के तत्वाधान में दो दिवसीय 18 से 19 अप्रैल को जिला स्तरीय प्रतियोगिता एम जे स्कूल कोहका भिलाई में हुआ। जिसमें जिले के लगभग 50 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में पहले दिन बच्चों के लिए ट्रेनिंग कैंप रखा गया एवं दूसरे दिन खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया गय। यह प्रतियोगिता की ओपनिंग सेरिमनी एमजी स्कूल की प्राचार्य श्रीमती मनप्रीत फूलमाली के द्वारा भगवान की अचर्ना कर उदघाटन किया गया ।

प्रतियोगिता के विजयी खिलाड़ियों में रम्य जैन गोल्ड, काव्य कुमारी सिल्वर, जैनराज गोल्ड, सार्थक साहू सिल्वर, शानवी जांघेल गोल्ड, माहिरा सिल्वर, मुग्धा चंद्राकर गोल्ड, मैली मधुकर सिल्वर, अनुराग बोस गोल्ड, कृतार्थ शांडिल्य सिल्वर, अमायरा राय गोल्ड, योगिता निषाद गोल्ड, नीतीश बांधे गोल्ड, कल्याण यादव गोल्ड , पंकज यादव गोल्ड, खुशी दिक्षीवार गोल्ड, सुयश चंद्राकर गोल्ड, अवनी चौबे गोल्ड, निशिता तिवारी गोल, आकृति सिंह गोल्ड हैं। वहीं रेफरशिप में ऐश्वर्या साहू, प्रवीण देवांगन, प्रियांशु बीसाई, अमन और कोच में नरेंद्र पांडे, इरफान अहमद, ज्योति साहब , बामन ऑफिशियल में जितेंद्र कुमार साहू तथा अर्जुन सोनी को मुख्य अतिथि किसान मोर्चा के अध्यक्ष मनीष वर्मा, सेना से सेवानिवृत जी शंकर राव और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन सिंह चौहान ने किया। पंचक सिलत मार्शल आर्ट एसोसिएशन सघ के महासचिव शेख समीर ने बताया कि राज्य मे नौकरी देने के लिए विचार चल रहा है। पूरे राज्य में इस खेल को अब खेला जा रहा है। विस्तार किया जा रहा है।

'लेने से नहीं, लौटाने से बनता है महान जीवन', यज्ञ क्रिया नहीं भाव है : आचार्य डॉ. अजय आर्य

यज्ञ बनो : अपने लिए नहीं, सबके लिए जीने का वैदिक मार्ग

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

लोकमंगल महायज्ञ के अवसर पर दिया गया प्रवचन यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को गहराई से उजागर करता है। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने की क्रिया नहीं बल्कि एक उच्च जीवन जीने की कला है। इसका मूल भाव है दूसरों के लिए जीना परोपकार करना और जीवन में अपने ऋण को चुकाना। जब तक यह भावना नहीं जागती तब तक कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता।

मनुष्य प्रकृति से निरंतर लेता है- वायु जल अन्न ऊर्जा,पर क्या उतना ही लौटाता है यही प्रश्न आज के दुःख का कारण भी है। सरल शब्दों में हम लेना जानते हैं देना अभी सीखना बाकी है। वेद का संदेश है—सौ हाथों से ग्रहण करो और हजार हाथों से लौटाओ अर्थात जितना मिला है उससे कई गुना समाज को लौटाने का संकल्प ही यज्ञ है।

प्रवचन में सहज और चुटीले ढंग से कहा गया आज इंसान इतना व्यस्त है कि कमाने का समय है खर्च करने का समय है लेकिन देने का समय नहीं है यही असंतुलन जीवन को अशांत बनाता है।

यज्ञ के गूढ़ अर्थ को समझाते हुए सहस्त्र शब्द की व्याख्या की गई। सहस्त्र का अर्थ केवल संख्या नहीं बल्कि अनेकता और व्यापकता है। जैसे सहस्त्रबाहु का अर्थ हजार भुजाएं नहीं बल्कि हजार भुजाओं के समान शक्ति होना है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी क्षमता का विस्तार करना चाहिए केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए। यज्ञ की सहस्त्रधारा को स्नेह की धारा बताया गया। जैसे घी अग्नि में समर्पित होता है वैसे ही जीवन में स्नेह सरलता और मधुरता का प्रवाह बना रहना चाहिए। कठोरता तो पत्थर में भी होती है महानता तो तरल बनने में है। जीवन में स्नेह की धारा टूटनी नहीं चाहिए।

प्रवचन में गहरे दार्शनिक भाव भी व्यक्त हुए कि एक में अनेक छिपा है व्यष्टि में समष्टि है और पिंड में ब्रह्मांड है। मनुष्य केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना का केंद्र है। हम सबके भीतर वही व्यापक सत्ता विद्यमान है इसलिए सीमित होकर भी हम असीम संभावनाओं से भरे हैं। जीवन को बदलने के सरल वैदिक सूत्र भी दिए गए-कम लो ज्यादा दो। स्वार्थ घटाओ सेवा बढ़ाओ। विचार बदलो जीवन बदल जाएगा। अपने लिए नहीं कुछ दूसरों के लिए भी जियो।

प्रवचन का सार यह रहा कि मनुष्य का शरीर नश्वर है लेकिन उसके कर्म और उनके फल अक्षय हैं। जो हम देते हैं वही हमारे पास लौटकर आता है कई गुना होकर। इसलिए यज्ञ केवल एक दिन का अनुष्ठान नहीं बल्कि हर दिन का आचरण होना चाहिए। आत्ममंथन का प्रश्न क्या हम जीवन को केवल अपने लिए जी रहे हैं या किसी और के जीवन में भी प्रकाश बन रहे हैं।

कार्यक्रम में राकेश दुबे द्वारा शंका समाधान सत्र का संयोजन किया गया। संतोष अग्रवाल एवं उनके परिवार ने मुख्य यजमान के रूप में सहभागिता निभाई। ओमप्रकाश जांगिड़ लोकेश साहू, वितीन शर्मा, संजय शर्मा, देवेश साहू, शैलेन्द्र गिरी, राघव, केशव सहित अनेक श्रद्धालुओं ने आहुति देकर इस आयोजन को सार्थक बनाया। शांति पाठ और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

खास खबर

प्रेरणादायक कदम : सुशील देशमुख का देहदान, एम्स रायपुर को चिकित्सा अध्ययन के लिए समर्पित

भिलाई। मानवता और सेवा भावना का एक प्रेरणादायक उदाहरण भिलाई में देखने को मिला, जहां भेलवा तालाब, कोहका निवासी स्वर्गीय सुशील देशमुख का मरणोपरांत देहदान किया गया। उनका पार्थिव शरीर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को चिकित्सा अध्ययन के लिए समर्पित किया गया, जिससे भविष्य के डॉक्टरों के प्रशिक्षण में सहायता मिलेगी। परिजनों के अनुसार, सुशील देशमुख ने अपने जीवनकाल में ही देहदान का संकल्प लिया था। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री देशमुख के साथ यह निर्णय लिया था और पिछले वर्ष प्रनाम संस्था के अध्यक्ष के माध्यम से विधिवत वसीयत भी तैयार करवाई थी।

उनके निधन की सूचना मिलते ही परिजनों ने ह्यप्रनामह्न संस्था को जानकारी दी, जिसके बाद संस्था के सहयोग से पूरे सम्मान और गरिमा के साथ देहदान की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान परिवार के सभी सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और इस निर्णय को समाज के लिए एक मिसाल बताया। इस पुनीत कार्य में राकेश देशमुख, विनय देशमुख, कमलाबाई, सावित्री देशमुख सहित अन्य परिजन उपस्थित रहे। साथ ही मनीष देशमुख, राम सोनी, राजू अमृत, करणवीर और अन्य लोगों ने भी सहभागिता निभाई। प्रनाम संस्था के स्वयंसेवकों ने पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराया।

संस्था का कहना है कि देहदान जैसे कार्य चिकित्सा शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और समाज में जागरूकता भी बढ़ाते हैं। संस्था ने लोगों से अपील की है कि वे भी इस दिशा में आगे आएं और मानवता की सेवा में योगदान दें। देहदान और अंगदान से संबंधित जानकारी या पंजीकरण के लिए इच्छुक लोग प्रनाम संस्था के हेल्पलाइन नंबर 9479273500 पर संपर्क कर सकते हैं। यह पहल समाज में सेवा, त्याग और मानवता का एक मजबूत संदेश देती है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आई है।

गुजरात से फोन कर बेटी ने पिता का देहदान कर पूरी की पिता की इच्छा

भिलाई। सुबोध कुमार चक्रवर्ती ने तीन वर्ष पूर्व नवदृष्टि फाउंडेशन के माध्यम से देहदान का संकल्प लिया था कल मध्य रात्रि सेक्टर 9 हॉस्पिटल में उनके निधन का समाचार मिलते ही उनकी पुत्री शिल्पी घोष चौधरी ने गुजरात से नवदृष्टि फाउंडेशन के सदस्यों को फोन कर पिता का देहदान कर उनकी इच्छा पूर्ण की परिवार के सदस्यों—पुत्री शिल्पी घोष चौधरी, पत्नी श्रीमती कल्पिता चक्रवर्ती एवं भांजे रंजीत चक्रबोर्ती—की सहमति से देहदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। नवदृष्टि फाउंडेशन के कुलवंत भाटिया एवं प्रभु दयाल उजाला ने वैशाली नगर स्थित निवास पहुंचकर देहदान प्रक्रीया में सहयोग किया।

श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. अंजलि वंजारी के निर्देशन में संदीप रिशवुड, दीपक रवानी एवं दयाराम की टीम द्वारा देहदान की प्रक्रिया पूर्ण की गई। स्वर्गीय चक्रवर्ती की पत्नी कल्पिता चक्रवर्ती ने बताया कि उनके पति ने जीवनकाल में सदैव समाज सेवा को महत्व दिया और देहदान का संकल्प भी उसी भावना से लिया था। आज उनके परिवार ने अपने मुखिया की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए यह पुण्य कार्य संपन्न किया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने स्वयं भी अपने पति के साथ देहदान का संकल्प लिया है। पुत्री शिल्पी घोष चौधरी ने भावुक होकर कहा कि पिता के निधन से पूरा परिवार गहरे सदमे में है, किन्तु उनकी अंतिम इच्छा को पूरा कर उन्हें गर्व एवं आत्मसंतोष की अनुभूति हो रही है। नवदृष्टि फाउंडेशन के प्रभु दयाल उजाला ने चक्रवर्ती परिवार के इस साहसिक निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम समाज में देहदान एवं नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कलेक्टर अभिजीत ने पीएम आवास योजना के कार्यों की समीक्षा की

रूचि नही लेने पर आवास स्वीकृति की जाएगी निरस्त

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सभी नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगर पालिका परिषद) एवं नगर पंचायत अधिकारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। उन्होंने हितग्राहियों को निर्माण कार्य में सक्रिय रूप से प्रेरित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में हितग्राहियों से सतत संपर्क बनाए रखते हुए निर्माण कार्यो की नियमित निगरानी करें, ताकि निर्धारित लक्ष्य समय पर प्राप्त किया जा सके।

कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवास निर्माण कार्यों को समय पर पूरा कर हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाए। जिन हितग्राहियों की निर्माण कार्य में रुचि नहीं है, उनकी बैठक लेकर उन्हें समझाइश दी जाए, इसके बावजूद रूचि नही लेने पर उनकी आवास स्वीकृति निरस्त करने की कार्यवाही करने को कहा। इसके साथ ही जिन हितग्राहियों ने अपने अंशदान की पूरी राशि जमा कर दी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास का पजेशन दिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

बैठक में अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और हितग्राहियों से निरंतर संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही ठेकेदारों को कार्य में तेजी लाने के लिए कहा गया। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी लंबित कार्यों को मई माह तक हर हाल में पूरा किया जाए, ताकि हितग्राहियों को शीघ्र लाभ मिल सके। बैठक में नगर निगम भिलाई आयुक्त राजीव पाण्डेय, नगर निगम दुर्ग आयुक्त सुमित अग्रवाल, नगर निगम भिलाई चरोदा आयुक्त दशरथ राजपूत, नगर निगम रिसाली आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा सहित सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे।

जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर निगम आयुक्त अग्रवाल की समीक्षा बैठक

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

- स्व-गणना सुविधा से जुड़े नागरिक, 16 से 30 अप्रैल तक पोर्टल रहेगा सक्रिय
- स्व-गणना सुविधा से नागरिकों को मिलेगा लाभ
- हर घर तक पहुंचे जनगणना, कोई भी न छूटे- आयुक्त

नगर पालिक निगम दुर्ग में जनगणना-2027 की तैयारियों के तहत निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल की अध्यक्षता में डाटा सेंटर में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नोडल अधिकारी, प्रभारी अधिकारी (जनगणना) एवं चार्ज अधिकारियों की उपस्थिति में जनगणना कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि नागरिकों की सुविधा हेतु स्व-गणना (Self Enumeration) की व्यवस्था आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in? पर 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उपलब्ध है। इसके माध्यम से नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनेगी।

आयुक्त सह प्रमुख नगर जनगणना अधिकारी श्री अग्रवाल ने निर्देश दिए कि जनगणना कार्य पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वाडवार घर-घर जाकर नंबरिंग सुनिश्चित करें और ध्यान रखें कि कोई भी घर छूटने न पाए। आमजन की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। निगम के सभी अधिकारियों और कमर्चारियों को स्व गणना करने हेतु आदेशित किए

आयुक्त ने डाटा सेंटर में कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रगणकों को जनगणना किट, निर्देश पुस्तिका एवं आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में उपायुक्त एवं चार्ज अधिकारी मोहेंद्र साहू सहित गिरीश दीवान, संजय ठाकुर, राजेन्द्र डबाले, आर.के. बोरकर, दुर्गेश गुप्ता, एस.के. केवलानी, हरिशंकर साहू, पंकज साहू, करण यादव, अपर्णा मिश्रा, उपयन्ति ठाकुर, प्रेरणा दुबे, सिद्धार्थ शर्मा, नारायण यादव, पंकज चन्द्रवंशी एवं गौतम साहू सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

भाजपा का विरोध प्रदर्शन : नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित न होने पर जताई नाराजगी

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

दुर्ग। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित न होने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार देर रात दुर्ग के हिंदी भवन के पास महात्मा गांधी पुतले के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रात करीब 9 बजे आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

कार्यक्रम में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पाण्डेय मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। उनके साथ जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक के मार्गदर्शन में प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान महापौर अलका बाघमार सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे।

प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और अपना आक्रोश व्यक्त किया।

इस अवसर पर सरोज पाण्डेय ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के विरोध के कारण यह महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं हो सका, जिससे महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ा। उन्होंने विशेष रूप से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के हितों की बात करने वाली पार्टी ने इस विधेयक का समर्थन नहीं किया, जिससे उनका दोहरा रवैया सामने आया है।

महापौर अलका बाघमार ने भी विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि इस अधिनियम का विरोध उनकी मानसिकता को दर्शाता है और आने वाले समय में देश की महिलाएं इसका जवाब देंगी। इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के विभिन्न पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिनमें जिला एवं मंडल स्तर के नेता, महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

दुर्ग में कांग्रेस का संगठन सृजन कार्य तेज 150 से अधिक बूथों पर कमेटियां गठित

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिला कांग्रेस कमेटी, दुर्ग शहर द्वारा संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा बूथ सशक्तिकरण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अभियान के तहत 5 ब्लॉक, 10 मंडल, 60 वार्ड एवं 275 बूथों में संगठन विस्तार का कार्य लगातार किया जा रहा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के मार्गदर्शन में चल रहे इस अभियान में ब्लॉक प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी एवं वार्ड स्तर के पदाधिकारियों के समन्वय से प्रत्येक बूथ पर कमेटियों का गठन किया जा रहा है। प्रतिदिन विभिन्न वार्डों में बैठकें आयोजित कर कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है और संगठन को मजबूत किया जा रहा है।

अब तक लगभग 150 बूथों पर बूथ कमेटियों का गठन किया जा चुका है, जबकि शेष बूथों पर कार्य प्रगति पर है। अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपते हुए उन्हें पार्टी की विचारधारा एवं जनहित के मुद्दों से जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। इस अभियान में ब्लॉक अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, आनंद ताम्रकार, देवश्री साहू, मनीष बघेल एवं गुरदीप सिंह भाटिया की सक्रिय भूमिका रही है। वहीं ब्लॉक प्रभारी अजय शर्मा, दुष्यंत देवांगन, प्रकाश जोशी, पोषण साहू एवं संजय बत्रा द्वारा क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

इस संबंध में जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने कहा कि, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मजबूत बूथ कमेटियां ही कांग्रेस की वास्तविक ताकत हैं। इसी के आधार पर हम जनता के मुद्दों को मजबूती से उठा सकते हैं और एक सशक्त संगठन का निर्माण कर सकते हैं। संगठन बहुत अच्छी तरह से अपन कार्य कर रही है , कार्यकर्ताओं पूरी ऊर्जा से जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान से कार्यकर्ता सीधे जनता से जुड़ रहे हैं, जिससे जनसमस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए संघर्ष करने में संगठन को मजबूती मिलेगी। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यह अभियान आगामी दिनों में और तेज किया जाएगा तथा सभी बूथों पर कमेटियों का गठन शीघ्र पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

डिजिटल प्रोजेक्ट प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल- बीएसपी द्वारा डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए बीएमडीसी, सेक्टर-7 में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से कुल 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य फोकस इंडेंटिंग विभागों अर्थात शॉप्स की भूमिका पर केंद्रित रहा, जिसमें आईपीयू की पहल से लेकर स्टेज-1 एवं स्टेज-2 अनुमोदन, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड, निष्पादन, कमीशनिंग तथा अंततः कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर तक की संपूर्ण प्रक्रिया को विस्तारपूर्वक समझाया गया। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को डीपीएमएस में पंजीकरण की प्रक्रिया, डायरेक्टरी निर्माण, कंसल्टेंट को असाइनमेंट, आईपीयू निर्माण, एमजेपो के साथ डीपीएमएस का इंटरफेस तथा विभिन्न अनुमोदन प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र कार्यशाला निदेशक पीके सरकार की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि डीपीएमएस के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी हितधारकों शॉप्स, कंसल्टेंट अथवा कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट विभाग के साथ समन्वित रूप से प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति का नियमित विश्लेषण करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक एमके गुप्ता, अनुराग उपाध्याय एवं उन्मेष भारद्वाज भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री अंकिता मोहनिया द्वारा किया गया। प्रशिक्षण का क्रियान्वयन उप महाप्रबंधक पुनीत वर्मा एवं सहायक महाप्रबंधक सुश्री जया तिवारी द्वारा किया गया, जिसमें आकाश मेश्राम, सुश्री चित्रांशी पटेल एवं प्रतीक शर्मा की सक्रिय सहभागिता रही। कार्यक्रम की पृष्ठभूमि का विवरण महाप्रबंधक सुश्री राधिका श्रीनिवासन द्वारा दिया गया व धन्यवाद ज्ञापन सहायक महाप्रबंधक सुश्री जया तिवारी द्वारा प्रस्तुत किया गया। सांयकालीन समापन सत्र में मुख्य महाप्रबंधक कार्तिकेय बेहेरा, मुख्य महाप्रबंधक तुलाराम बेहेरा तथा मुख्य महाप्रबंधक एमके गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति रही।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर छग को राष्ट्रीय स्तर पर मिले दो प्रतिष्ठित पुरस्कार

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रभावी, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 17 एवं 18 अप्रैल 2026 को पुणे (महाराष्ट्र) में आयोजित चिंतन शिविर में देश के सभी राज्यों के मध्य छत्तीसगढ़ को "बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य" (Best Performing Large State) के रूप में दो प्रतिष्ठित श्रेणियों में सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ को हाई ट्रिगर एफिकेसी श्रेणी में संदिग्ध क्लेम की सटीक पहचान और उनके प्रभावी विश्लेषण के लिए तथा टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ सस्पिशियस क्लेम्स श्रेणी में संदिग्ध दावों के त्वरित और समयबद्ध निपटान के लिए यह सम्मान प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ में उन्नत आईटी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम, सुदृढ़ क्लेम ऑडिट तंत्र तथा ट्रिगर-आधारित निगरानी प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते संदिग्ध प्रकरणों की समय पर पहचान और उनके त्वरित निराकरण में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। अस्पतालों के साथ बेहतर समन्वय और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से क्लेम प्रोसेसिंग की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है तथा अनावश्यक विलंब में कमी आई है, जिससे योजना के लाभार्थियों को समयबद्ध, सहज और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित हो रही हैं। यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी सुदृढ़ता को दर्शाती है, बल्कि प्रदेश सरकार की जनकेन्द्रित सोच और सेवा-भावना को भी प्रतिबिंबित करती है।

इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ को मिला यह राष्ट्रीय सम्मान राज्य की पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेन्द्रित स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, और इसी दिशा में तकनीक आधारित मॉनिटरिंग, सुदृढ़ प्रबंधन और सतत सुधार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, स्वास्थ्यकर्मियों और सभी सहयोगी संस्थानों को देते हुए विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ भविष्य में भी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करता रहेगा।

इस अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य तंत्र की प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और निरंतर सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए संकल्पित है और यह उपलब्धि स्वास्थ्यकर्मियों प्रशासनिक टीम तथा सभी सहयोगी संस्थानों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जनसेवा को सवीच्च प्राथमिकता देता रहेगा।

खास खबर

27 एकड़ में विकसित होगा नया औद्योगिक क्षेत्र : कोरबा के विकास को मिलेगा नया आयाम-मंत्री लखन लाल

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मंत्री लखन लाल के मुख्य आतिथ्य में गोपालपुर में नए औद्योगिक क्षेत्र का हुआ भूमिपूजन

वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य में कोरबा जिले के दर्री तहसील अंतर्गत ग्राम गोपालपुर में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमिपूजन समारोह का आयोजन हुआ। मंत्री श्री देवांगन द्वारा विधिवत पूजा-अर्चना के साथ अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। यह औद्योगिक क्षेत्र लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करते हुए क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ पवन सिंह, कलेक्टर कुणाल दुदावत, प्रबंध निदेशक सीएसआईडीसी रायपुर विश्वेश कुमार, निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, सहित अन्य जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी, चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

मंत्री श्री देवांगन ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि गोपालपुर में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमिपूजन केवल एक परियोजना की शुरुआत नहीं, बल्कि कोरबा के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है। कोरबा के लिए गर्व की बात है, वर्ष 1980 के बाद आज जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। लगभग 10.900 हेक्टेयर (27 एकड़) भूमि पर 10.59 करोड़ की लागत से विकसित होने वाला यह औद्योगिक क्षेत्र कोरबा जिले के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा। इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में उद्योगों के विस्तार और अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।

सीएसआईडीसी के अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य की नई औद्योगिक नीति युवाओं और नवोदित उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है, जिससे नए उद्योग स्थापित हों और व्यापक रोजगार के अवसर सृजित हों। गोपालपुर के इस नवीन औद्योगिक क्षेत्र में 44 इकाइयों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इससे यहां औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी और स्थानीय युवाओं को यहीं पर रोजगार के अवसर मिलेंगे।

उन्होंने बताया कि नीति के अंतर्गत उद्योगों को आकर्षित करने के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। साथ ही, पात्र इकाइयों को विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से कुल निवेश का लगभग 65 प्रतिशत तक सहायता/अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरबा अब केवल कोयला और विद्युत उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे विविध उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अंत में उन्होंने सभी उद्यमियों को शुभकामनाएँ दीं।

एमडी श्री कुमार ने लगभग 11 हेक्टेयर क्षेत्र में नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास की घोषणा करते हुए सभी को शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने बताया नवीन औद्योगिक एरिया विकास की प्रस्तावना से लेकर टेंडर कार्य प्रक्रिया में है। कार्यों को पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। नई औद्योगिक नीति के तहत एमएसएमई, नए उद्योगों और स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने में सहायता मिलेगी और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे। साथ ही, वन क्लिक सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को सरल, तेज और सुगम बनाया गया है, ताकि निवेशकों और उद्यमियों को एक ही मंच पर सभी सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।

विश्व धरोहर दिवस पर रायपुर में सजी विरासत की अनोखी झलक, संरक्षण पर हुई विशेषज्ञों का मंथन

सोमनाथ से छत्तीसगढ़ के मंदिरों तक सांस्कृतिक यात्रा, आपदा के दौर में धरोहर संरक्षण पर जोर

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

संस्कृति विभाग अंतर्गत पुरातत्त्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय, रायपुर द्वारा विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में चित्र प्रदर्शनी एवं व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं संचालक पुरातत्व एवं संस्कृति विवेक आचार्य के निर्देशन में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के वरिष्ठ इतिहासकार प्रो. रमेंद्रनाथ मिश्र, अतिथि वक्ता डॉ. राम सतीश पुसुपुलेटी तथा पवन जोशी द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्वानों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों की सहभागिता रही।

संचालनालय द्वारा प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस पर ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक स्थलों एवं परंपराओं के संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने और सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में इस वर्ष भी प्रदर्शनी और व्याख्यान के माध्यम से विरासत संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायक पहल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व झ अटूट आस्था के 1000 वर्ष का अनुसरण करते हुए कला वीथिका में विशेष चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में सोमनाथ मंदिर के 19वीं, 20वीं और 21वीं सदी के चित्रों के माध्यम से उसके ऐतिहासिक विकास, स्थापत्य परिवर्तन और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रमुख शिव मंदिरों की स्थापत्य कला को प्रदर्शित करते चित्र भी आकर्षण का केंद्र रहे। स्थानीय धरोहरों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से जोड़ने का यह प्रयास दर्शकों के लिए विशेष रूप से ज्ञानवर्धक रहा।

इस वर्ष विश्व धरोहर दिवस 2026 की थीम इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर्स पर आधारित व्याख्यान सत्र भी आयोजित किया गया। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ. संतोष कुमार, आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर डॉ. राम सतीश पुसुपुलेटी तथा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के डिप्टी कमांडेंट पवन जोशी ने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए।

विशेषज्ञों ने मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों पर मंडराते खतरों, उनके प्रकार, संरक्षण की चुनौतियों तथा आपदा प्रबंधन के प्रभावी उपायों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि धरोहर संरक्षण में शासन के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में प्रदेश के प्रमुख मंदिरों—दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा, महामाया मंदिर रतनपुर, राजीवलोचन मंदिर राजिम, सहसपुर स्थित शिव एवं बजरंगबली मंदिर तथा लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद के ट्रस्ट एवं समिति के पदाधिकारियों ने भी सहभागिता की।

इस अवसर पर कळळअउल रायपुर चैप्टर के संयोजक अरविंद, एके सिंह, श्रीश मिश्र सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम प्रभारी डॉ. पीसी पारख, उप संचालक एवं विभागीय अधिकारियों—डॉ. अरुंधति परिहार, प्रवीन तिर्की, भीरेंद्र धीवर, विक्रांत वैष्णव, डॉ. राजीव मिंज, अमर भरतद्वाज, नूतन एक्का और अरुण निर्मलकर की सक्रिय भूमिका रही। कार्यक्रम का सफल संचालन पुरातत्ववेत्ता प्रभात कुमार सिंह ने किया।

यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सफल रहा, बल्कि आधुनिक समय में आपदाओं और संकटों के बीच धरोहरों की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

वालंटियर्स की सहभागिता से जागरूकता अभियान को मिलेगा बल

विश्व रेडक्रॉस दिवस पर राज्यभर में रंगारंग कार्यक्रम

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आगामी 8 मई को राज्य स्तर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में रेडक्रॉस राज्य शाखा, रायपुर के चेयरमैन श्री तोमन साहू की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस भवन में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि इस विशेष अवसर पर समूह नृत्य, प्रहसन एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेशभर के रेडक्रॉस वालंटियर्स भाग लेंगे। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान रेडक्रॉस की गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु विस्तृत कार्ययोजना भी तैयार कर जारी की गई। योजना में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने, विशेष अवसरों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा अधिक से अधिक लोगों को प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है। साथ ही, रक्तदान शिविरों का व्यापक आयोजन कर रक्त की आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित करने और रक्तदान महादान के संदेश को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जूनियर रेडक्रॉस एवं यूथ रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से विद्यार्थियों को रचनात्मक और सेवा आधारित गतिविधियों से जोड़ने की भी योजना बनाई गई है, जिससे उनमें मानवीय मूल्यों और सेवा भाव का विकास हो सके। जिला शिक्षा अधिकारियों को माहवार गतिविधियों के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए गए हैं।

कार्ययोजना में शैक्षणिक भ्रमण, प्राकृतिक अध्ययन, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, काउंसलर प्रशिक्षण, ट्रैकिंग कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण जागरूकता, रक्तदाता दिवस, विश्व योग दिवस, जनसंख्या दिवस, साक्षरता दिवस, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, दिव्यांग दिवस, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण सहित विभिन्न कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। साथ ही, विद्यार्थियों को नई दिल्ली में लोकसभा एवं राज्यसभा की कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए शैक्षणिक भ्रमण भी प्रस्तावित है। बैठक में चेयरमैन तोमन साहू, कोषाध्यक्ष संजय पटेल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मिशन कर्मयोगी के तहत संस्थागत क्षमता निर्माण कार्यशाला का हुआ आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

क्षमता विकास आयोग, भारत सरकार के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर द्वारा मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत एक दिवसीय संस्थागत क्षमता निर्माण कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ शासन के लगभग 40 विभागों के नोडल अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी तथा क्षमता विकास आयोग, नई दिल्ली के पर्यवेक्षक ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

कार्यशाला को चार थीम आधारित सत्रों में विभाजित किया गया था। उद्घाटन सत्र में सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अविनाश चंपावत ने कार्यशाला के औचित्य, उद्देश्य एवं लक्ष्यों पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए क्षमता निर्माण की आवश्यकता और प्रशासनिक दक्षता के

महत्व पर प्रकाश डाला।

प्रथम सत्र में विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए गए। आईएएस अधिकारी कार्तिकेय गोयल ने रोल आधारित क्षमता निर्माण एवं प्रदर्शन विषय पर अपने विचार साझा किए। प्रशासन अकादमी के महानिदेशक एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुब्रत साहू ने प्रशिक्षण संस्थानों की शक्ति आधारित भूमिका पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। ट्रिपल आईटी रायपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर ओपी व्यास ने अकटेकनोलॉजी के उपयोग एवं शिक्षण पद्धति विषय पर नवीन तकनीकी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वहीं, आई-गॉट कमयोगी की स्टेट नोडल ऑफिसर एवं अवर सचिव श्रीमती अंजू सिंह ने राज्य में कैडर आधारित प्रशिक्षण व्यवस्था की जानकारी दी।

द्वितीय सत्र में सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को चार समूहों में विभाजित कर थीम आधारित प्रेजेंटेशन तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात तृतीय सत्र में समूहों द्वारा अपने-अपने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए गए, जो इस कार्यशाला का प्रमुख आकर्षण रहा।

इसी क्रम में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की नोडल अधिकारी डॉ. अनुराधा दुबे ने अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर संस्थागत प्रशिक्षण की भूमिका, उद्देश्य, लक्ष्य, चुनौतियां एवं समाधान विषय पर एक समग्र प्रस्तुति दी। इस प्रेजेंटेशन में पर्यटन विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी प्रमील वर्मा, आईएचएम रायपुर की प्रोफेसर श्रीमती प्रिया शर्मा, सीनियर मैनेजर आईटी विकेश ऊके सहित महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मत्स्य, पशुपालन, खेल एवं युवा कल्याण, वाणिज्य एवं उद्योग तथा परिवहन विभाग के प्रतिनिधियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

कार्यशाला का समापन चतुर्थ सत्र में प्रशासन अकादमी के महानिदेशक श्री सुब्रत साहू के प्रेरक समापन उद्बोधन के साथ हुआ। कार्यक्रम के अंत में डायरेक्टर श्री महावर ने सभी प्रतिभागियों एवं आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। यह कार्यशाला प्रशासनिक क्षमता विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है, जिससे विभागों के बीच समन्वय, नवाचार और दक्षता को नई दिशा मिलेगी।

वीआईपी रेस्टहाउस में 'मौज' करते अफसर, मंत्री के सामने खुली पोल, कार्रवाई के निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / कोरबा

सरकारी संपत्तियों के उपयोग को लेकर सवाल खड़े करने वाली एक और तस्वीर सामने आई है। जिले के बी-टाइप वीआईपी रेस्टहाउस में विभागीय अधिकारियों की शराब पार्टी ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप है कि डीएसपीएम के चीफ केमिस्ट गोवर्धन सिदार अपने साथ चार अन्य अधिकारियों के साथ कमरे में बैठकर शराबखोरी करते पाए गए।

मामला तब उजागर हुआ जब पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक के कोरबा प्रवास के दौरान उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, महापौर संजू देवी राजपूत और जिला भाजपा अध्यक्ष गोपाल मोदी उनसे मिलने रेस्टहाउस पहुंचे थे। इसी दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मंत्री को सूचना दी कि वीआईपी कमरे में कुछ अधिकारी शराब पार्टी कर रहे हैं।

कमरे में बोतलें, किचन में बीयर, धुएं से भरा माहौल

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कमरे के अंदर शराब की खाली बोतलें, चखना और पानी फैला हुआ था। हालात ऐसे थे मानो सरकारी रेस्टहाउस नहीं, बल्कि निजी पार्टी का अड्डा हो। इतना ही नहीं, रेस्टहाउस के किचन के फ्रीजर में बीयर की बोतलें भी रखी मिलीं। कमरे में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था और अधिकारी खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए।

मंत्री ने लिया संज्ञान, एमडी को फोन

मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री लखन लाल देवांगन ने तत्काल संबंधित उत्पादन कंपनी के एमडी एसके कटियार को फोन कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

सीमेंट फैक्ट्री विवाद से जोड़कर देख रहे लोग

यह घटना एक बड़ा सवाल छोड़ गई है—क्या सरकारी रेस्टहाउस अब अधिकारियों के लिए ऐशगाह बनते जा रहे हैं? जहां आम जनता के लिए बने संसाधनों का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। घटना ने न केवल प्रशासनिक अनुशासन पर सवाल उठाए हैं, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे कुछ अधिकारी नियम-कायदों को किस तरह ताक पर रख रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है या वास्तव में जिम्मेदारों पर शिकंजा कसता है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव नगरीय निकायों के कार्यों की करेंगे समीक्षा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव राजधानी रायपुर में दो दिनों तक मैराथन बैठक कर राज्य के सभी नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। वे इस दौरान सभी निकायों में विकास कार्यों की प्रगति तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निगम आयुक्तों तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अपने वरिष्ठ अभियंताओं के साथ बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं।

श्री साव रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस कन्वेंशन-हॉल में 20 अप्रैल को सवेरे 10 बजे से प्रदेश के सभी नगर निगमों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। वे दोपहर ढाई बजे से नगर पालिकाओं के कार्यों की समीक्षा करेंगे। श्री साव अगले दिन 21 अप्रैल को दिनभर संभागवार सभी नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इन कार्यों और योजनाओं की होगी समीक्षा

उप मुख्यमंत्री अरुण साव दो दिवसीय मैराथन बैठक के दौरान नगरीय निकायों में राजस्व वसूली, विद्युत देयकों के भुगतान, वेतन भुगतान, अधोसंरचना विकास व 15वें वित्त आयोग के कार्यों, नालंदा परिसरों, नगरोत्थान योजना, जलप्रदाय योजनाओं, आपदा प्रबंधन, गोधाम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, आई-गॉट कर्मयोगी तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों की समीक्षा करेंगे।

संपादकीय

अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं बढ़ रही हैं

अर्थव्यवस्था का संकट बढ़ रहा है। दरअसल, जड़ कमजोर हो, तो आंधी अधिक भयानक मालूम पड़ने लगती है। यही भारत की मौजूदा हकीकत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं भारत सरकार को मालूम ना रही हों।

चिंता की कोई बात ना होने जैसे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के आश्वासनों के बावजूद हकीकत यही है कि खुद केंद्र गहरी चिंता में है। इसका प्रमाण वित्त मंत्रालय की ताजा मासिक समीक्षा रिपोर्ट है। इसमें अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद जोखिमों का साफ-साफ जिक्र किया गया है। स्वीकार किया गया है कि इस महीने आर्थिक गतिविधियां धीमी हुई। हालांकि इसके केवल घरेलू कारण भी हैं, मगर खासकर पश्चिम एशिया में युद्ध और ऊर्जा आपूर्ति की अनिश्चितताओं से समस्या बेहद गहरी हो गई है। इस कारण सबसे बड़ी चिंता खाद्य पदार्थों की महंगाई को लेकर खड़ी हुई है। बढ़ती कीमतें ग्रामीण और शहरी गरीब वर्ग पर असमान असर डाल रही हैं।

ऊर्जा लागत में वृद्धि से महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। इसके अलावा व्यापार घाटा और चालू खाते का घाटा बढ़ रहा है। विदेशी निवेश में सुस्ती से रुपये पर दबाव है, जिससे वित्तीय बाजारों में अस्थिरता का खतरा बढ़ा है। यानी समस्या चौतरफा है। जब जड़ कमजोर हो, तो आंधी अधिक भयानक मालूम पड़ने लगती है। यही भारत की मौजूदा हकीकत है। ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं सरकार को मालूम ना रही हों। खुद मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन इनको लेकर आगाह करते रहे हैं, जिन्होंने ताजा समीक्षा रिपोर्ट तैयार की है। मसलन 2025 में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि वित्तीय क्षेत्र का अनियंत्रित विकास वास्तविक अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। पिछले वर्ष उन्होंने कहा कि भारत में आईपीओ प्रवर्तक निवेशकों के लिए निकास का साधन बन गए हैं।

यानी ये पूंनिवेश का साधन नहीं रहे। इस वर्ष जनवरी में पेश आर्थिक सर्वे में कहा गया कि भारतीय निक्षेत्र जोखिम उठाने को तैयार नहीं है और वह अनुसंधान एवं विकास के इंजन को आगे बढ़ाने में विफल रहा है। इसके बावजूद निक्षेत्र एवं वित्तीय आथिर्की को केंद्र में रखते हुए ऊंची जीडीपी वृद्धि दर को भारतीय अर्थव्यवस्था की खास पहचान बनाया गया। मगर ये खंभे रेत पर खड़े हैं। अब चूंकि परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई हैं, तो ये डोलते नजर आ रहे हैं। मासिक समीक्षा रिपोर्ट का सार-संक्षेप यही है।

संवादहीनता के चलते महिला आरक्षण पर लगा गतिरोध

ज्योति मलहोत्रा

विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। दरअसल, इस बार नए विधेयक पर आम सहमति न तो चाही गई और न ही हासिल की गई क्योंकि इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में परस्पर बातचीत नहीं हुई। जबकि 2023 में कांग्रेस समेत विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम एकमत से पास कराने में भाजपा का साथ दिया था।

भारतीय राजनीति में महिला वोट बैंक बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उल्लेखनीय परियोजना, जिसके जरिए वे जाति और वर्ग, दोनों की राजनीति को पछाड़ने की उम्मीद रखे हुए हैं, पिछले 12 सालों में वह कल्पनातीत रूप से काफी कारगर रही है। मोदी ने हाल के दिनों में किसी भी दूसरे पुरुष नेता से ज़्यादा महिलाओं की शिकायतें सुनने का प्रयास किया है- शुरुआत गांव के छोटे घरों में इस्तेमाल होने वाले, धुआं पैदा करने वाले चूल्हों को उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस सिलेंडर से बदलने की मुहिम से हुई, और फिर उनके बैंक खाते में पैसे डाले गए, खासकर उनके राज्यों में चुनावों से पहले।

तो फिर, महिला आरक्षण बिल, जिसे पेश करने की अगुवाई प्रधानमंत्री ने लोकसभा में की, यहां तक कि कुछ राज्यों में जारी चुनाव प्रचार के बीच में संसद का विशेष सत्र बुलाया, वह स्वीकृत क्यों नहीं हो पाया? क्या भारत की महिलाएं राष्ट्रीय नारी शक्ति का हिस्सा नहीं बनना चाहतीं? इसका जवाब जटिल है, जाहिर है, शुरुआत इस तथ्य से होगी कि देवियों में हमारी गहरी आस्था के बावजूद, दुर्गा से लेकर काली, सरस्वती और लक्ष्मी और भी बहुत सारी, आप पूछ सकते हैं कि भारत में पुरुष-प्रधान समाज की जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं। अवश्य ही, हम महिलाएं ही उन जड़ों को सींचने और अपना ही नुकसान करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। वरना हरियाणा में महिला-पुरुष अनुपात (879/1,000), पंजाब (895/1,000) व दिल्ली (868/1,000) न होता —मानें या न मानें, 1000 पुरुषों पर 818 महिलाओं के साथ चंडीगढ़ का आंकड़ा देशभर में सबसे नीचे है, राष्ट्रीय सूची में ये सब नीचे क्यों है? (हालांकि हरियाणा का दावा है कि पिछले साल उसका आंकड़ा बढ़कर प्रति 1,000 पुरुषों पर 914 महिलाएं हो गया है।)

सवाल उठता है कि केरल के बराबर आबादी वाला पंजाब, दोनों की आबादी लगभग 3 करोड़ है, लिंगानुपात के पैमाने पर देशभर में दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य क्यों है? केरल (1,084), तमिलनाडु (996), आंध्र प्रदेश और कर्नाटक (दोनों 993) जैसे दक्षिणी राज्यों का प्रदर्शन उत्तरी राज्यों की तुलना में इस पैमाने (और अन्य कई सामाजिक-आर्थिक मापदंडों पर भी) इतना बढ़िया क्यों है? दूसरा सवाल पूछना बनता है कि विपक्षी दल महिला आरक्षण बिल के खिलाफ क्यों हैं? उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लाए उस विधान का समर्थन क्यों नहीं किया, जिससे भारतीय राजनीति में उलटफेर होना तय है? क्या विपक्ष महिला विरोधी है?

पिछले कुछ दशकों में महिला आरक्षण कानून का सफर काफी लंबा रहा, जैसा कि मेरी सहयोगी सूर्या पिल्लई ने इस विषय पर कुछ दिन पहले बहुत बढ़िया लिखा था। सच तो यह है कि 2008 में कांग्रेस नीत यूपीए ने ही संसद में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पेश किया था, और सुनिश्चित किया कि 2010 में पास हो जाए, राज्य सभा में भी, ताकि यह लैप्स न हो (तय अवधि में पास होना अनिवार्य है, परंतु जब कोई कानून राज्यसभा में पास हो जाए, तब लैप्स नहीं होता)। कांग्रेस को अहसास था कि महिला आरक्षण बिल पर उसकी अपनी यूपीए बंटी हुई है (आरजेडी नेता शरद यादव ने पर कटी महिलाएं जैसा कटाक्ष किया था और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने तो यह तक कह डाला कि अगर संसद महिला आरक्षण कानून पास कर देगी तो यह उन महिलाओं के लिए दरवाजे खोल देगा जिन पर फब्ती कसी जाती और सीटियां बजती हैं, ये बिल पर आपसी मतभेद दर्शाता है), जिसका मतलब था कि उसके पास अपने समय की लोकसभाओं में इसे पास करा लेने को कभी भी पर्याप्त संख्या नहीं रही, लिहाजा उन्होंने दूसरा बेहतर विकल्प चुना।

कांग्रेस के जोर देने पर मोदी सरकार ने 2023 में यह काम आगे बढ़ाया और सुधार करने के बाद कानून पास किया गया। इसीलिए 2023 में, कांग्रेस और बाकी विपक्ष ने, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एकमत से पास कराने में भाजपा का साथ दिया। और 2026 के बिल में भी यही संदेश मिलना चाहिए था- आम सहमति। जिस प्रकार 2023 में पूरी संसद इस मुद्दे पर सर्वसम्मत थी- केवल दो सांसदों ने बिल के खिलाफ वोट दिया था- संसद में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के समर्थन में। इस बार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और शेष वरिष्ठ भाजपा नेतृत्व को चाहिए था कि विपक्ष को बुलाकर महिला आरक्षण बिल पर उनका समर्थन मांगते। यह भी हो सकता था कि एक संयुक्त संसदीय समिति या कोई विशेष समिति, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि होते, इस कानून की तमाम धाराओं पर बारीकी से बहस करते -मसलन, क्या इसमें अन्य पिछड़ी जातियों और दलित महिलाओं के लिए ह्यकोटे के अंदर कोटाह्न होगा?- और एक बार आम सहमति बन जाने के बाद, नया कानून और उसे लागू करने की रूपरेखा को सदन में रखा जाता।

बदकिस्मती से, न तो आम सहमति बनानी चाही और न ही हासिल की जा सकी क्योंकि कोई संवाद नहीं हुआ। इन दिनों संसद इस कदर बंटी हुई है कि सांसद एक-दूसरे से अपमानजनक रूप से बोल रहे हैं, इसके लिए एक बड़े दिल वाले और छोटे अहम वाले नेता की जरूरत है, जो छोटी-मोटी बातों और चालबाजियों को भुलाकर दूसरे पक्ष से मेल-मिलाप रखे और संवाद करे।

साफ है, महिला आरक्षण बिल का भी वही हाल हुआ है जो 2020 में तीन कृषि कानूनों का हुआ था। ठीक वैसे ही जिस प्रकार केंद्र को तीनों कानून वापस लेने पड़े, क्योंकि उन्हें लाने से पहले किसान संगठनों और राजनीतिक दलों के साथ बहुत कम संवाद या चर्चा की गई थी -शायद पंजाब के एक हिस्से में बतौर पायलट प्रोजेक्ट इन कृषि कानूनों का प्रयोग किया जा सकता था, जिससे दोनों पक्षों को कोई राह मिल जाती- उसी तरह सत्ता पक्ष महिला आरक्षण कानून पास कराने लायक संख्या नहीं जुटा पाया।

प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता से कह सकते थेः ह्यआइए मिलकर इतिहास लिखें। अब समय आ गया है कि महिलाएं कम से कम एक-तिहाई आसमान छूएं। यूं तो देश की कुल आबादी में महिलाओं की गिनती 48-49 प्रतिशत है, लेकिन शुरुआत के लिए, उन्हें 33 फीसदी देते हैं। इसपर विपक्ष के नेता का जवाब होताः हां, चलिए, हम साथ हैं। दुर्भाग्यवश, मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और के. कनिमोझी अपनी-अपनी दलीलें देते रहे। संसद किस हद तक बदल गयी है, यह तब साफ हो गया जब प्रियंका गांधी-अमित शाह की एक-दो टिप्पणियां- जिन्हें पुराने दिनों में संसदीय बहस में सलीके से बात काटने और हाजिर जवाबी का आम तरीका माना जाता था। इस पर कुछ सांसद हंसने लगे, कुछ तो घबराए से भी। सत्ता और विपक्ष के बीच संवाद की कमी से संसद में महिलाओं के मुद्दे पर टकराव हो गया।

एक और अहम बात यह कि शुक्रवार शाम को कानून में संवैधानिक संशोधन असफल रहने के 24 घंटे से भी कम समय पहले, सरकार ने गुरुवार देर शाम 2023 नारी शक्ति अधिनियम अधिसूचना जारी कर दी थी। इसका मतलब है कि कानून अभी सक्रिय है और इसे कभी भी लागू किया जा सकता है। बिखराव के इस समय में, यह आखिरी प्रयास उम्मीद जगाता है।

महिला आरक्षण का बिल गिरा- या संसद की गरिमा गिरी?

आचार्य डॉ. अजय आर्य

यह केवल एक विधेयक के गिरने की घटना नहीं है, यह संसद की संवेदनशीलता, उसकी नीयत और उसकी प्राथमिकताओं के गिरने का प्रतीक है। जब आधी आबादी के अधिकार पर भी राजनीति हावी हो जाए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है—क्या सच में बिल गिरा है या हमारी लोकतांत्रिक आत्मा?

भारतीय संस्कृति ने तो हजारों वर्ष पहले ही स्पष्ट कर दिया था—'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहीं देवत्व बसता है। लेकिन आज की राजनीति इस आदर्श को मानने के बजाय उससे मुँह मोड़ती दिख रही है।

स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के आधार पर नारी को समान अधिकार देने की बात की थी। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने अपने समय में कुरीतियों से लड़कर महिलाओं को सम्मान और अधिकार दिलाए। आज जब लोकतंत्र अपने परिपक्वहोने का दावा करता है, तब वही अधिकार देने में हिचक क्यों?

यह वही देश है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने शौर्य की मिसाल कायम की, सरोजिनी नायडू ने स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व किया, और इंदिरा गांधी ने देश की बागडोर संभाली। फिर भी संसद में महिलाओं को उनका अधिकार देने पर बहस, बहाने और टालमटोल—यह केवल विरोध नहीं, बल्कि सोच की दरिद्रता है।

महिला आरक्षण पर विरोध के नाम पर जो तर्क दिए जाते हैं—'योग्यता प्रभावित होगी', 'आरक्षण के भीतर आरक्षण चाहिए', 'यह राजनीतिक लाभ का प्रयास है'—ये सभी तर्क उस असली डर को छुपाते हैं, जो सत्ता में हिस्सेदारी कम होने का है।

जब हम महिलाओं को 'आधी आबादी' कहते हैं, तो उनका अधिकार भी कम से कम 50% होना चाहिए। फिर 33% पर भी इतना शोर क्यों? और जो दल महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, वे अपनी ही पार्टी में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देते?

नगर निकायों में आरक्षण सबको स्वीकार है, क्योंकि वहाँ सत्ता सीमित है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा—जहाँ वास्तविक शक्ति है—वहाँ महिलाओं का रास्ता रोका जाता है। यह विरोध नहीं, बल्कि अवसरों की चौकीदारी है।

'नेता जी कहते हैं—हम महिलाओं का सम्मान करते हैं- बस उन्हें बराबरी पर देखने की आदत नहीं है!' 'मंच पर 'बहन-बेटी' कहना आसान है, पर सत्ता में भागीदारी देना इतना कठिन क्यों? 'सम्मान भाषणों से नहीं, हिस्सेदारी से साबित होता है।' 'नारी को प्रतीक नहीं, सत्ता में स्थान चाहिए।'

आज जरूरत है आक्रोश की, सवालों की और स्पष्ट निर्णय की। अगर संसद महिलाओं को उनका अधिकार देने में असफल होती है, तो यह केवल एक विधेयक की हार नहीं, बल्कि उस सोच की हार है जो समानता की बात करती है।

अब प्रश्न सीधा है—महिला आरक्षण गिरा है या संसद की गरिमा?

(लेखक आर्य जगत के सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान एवं विचारक हैं।)

महतारी वंदन योजना : पहाड़ी कोरवा परिवारों की तकदीर, बकरी पालन बना आजीविका का सशक्त माध्यम

डॉ. अनु कुमार

प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप 'महतारी वंदन योजना' प्रदेश की महिलाओं के लिए न केवल आर्थिक संबल, बल्कि स्वावलंबन का नया आधार बन रही है। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की श्रीमती करियो के जीवन में आई खुशहाली लेकर आई है। अम्बिकापुर विकासखण्ड के ग्राम रामनगर की रहने वाली श्रीमती करियो ने योजना से प्राप्त सहायता राशि का सदुपयोग कर न केवल अपना भविष्य संवारा है, बल्कि अपने पूरे परिवार की स्थिति को बेहतर बनाया है।

योजना की राशि को बनाया आत्मनिर्भरता माध्यम

श्रीमती करियो बताती हैं कि पहले उनके परिवार की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। दैनिक खर्चों के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता था। महतारी वंदन योजना के लागू होने के बाद, जब उनके खाते में राशि आनी शुरू हुई, तो उन्होंने इसे घरेलू खर्चों में लगाने के बजाय निवेश का रास्ता चुना। उन्होंने इस राशि को सहेज कर बकरियां खरीदीं और पशुपालन शुरू किया।

बकरी पालन से मिली आर्थिक मजबूती

अपनी सफलता साझा करते हुए श्रीमती करियो ने बताया कि मैंने योजना के पैसों से बकरियां खरीदीं और साल भर उनकी देखभाल की। अब मेरे पास छह बकरियां हैं। बकरियां समय-समय पर बच्चे देती हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब मुझे इनसे निरंतर लाभ मिल रहा है और मैंने अपना गुजारा इन्हीं के माध्यम से सुरक्षित कर लिया है।

परिवार की खुशहाली और बेहतर खान-पान

आर्थिक स्थिति सुधरने से श्रीमती करियो अब अपने पति और नाती-पोतों की बेहतर देखभाल कर पा रही हैं। वे कहती हैं कि पहले और अब के जीवन में बड़ बड़ा बदलाव आ गया है। अब घर में अच्छा खान-पान है और बच्चों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, यह सब सरकार की मदद से संभव हो पाया है, वरना हमारे लिए यह सब सोच पाना भी कठिन था।

योजना के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभार

अपनी और अपने परिवार की बदलती तस्वीर देख श्रीमती करियो ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना ने उन्हें समाज में सम्मान से जीने का अवसर दिया है। उनके अनुसार, यह योजना ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

उगते सागर ने बचपन छीन बढ़ाए बाल विवाह

अमरेंद्र किशोर

सुंदरबन जैसे इलाके में बड़ी संख्या में किशोरियों की शादी मात्र 'परंपरा' नहीं। यह कमजोर आर्थिक हालत में जीवन-रक्षा की रणनीति है। समुद्र में बार-बार चक्रवात आने, तटबंध टूटने, खारी मिट्टी से कृषि व मछली पालन प्रभावित होता है, जिससे आजीविका पर संकट आने से बाल-विवाह बढ़ते हैं।

सुंदरबन इलाके में जब सागर की लहरें धीरे-धीरे दलदली मिट्टी पर आती हैं- नमक और तूफान की तीव्रता से बंधा तट कांपता है, वहां बचपन की मासूमियत भी खतरे में पड़ जाती है। यहां गांवों में, घर की दीवारें धंसती मिट्टी पर टिकी हैं। इस संकट में सबसे अधिक प्रभावित होती हैं लड़कियां, जिनकी उम्र के सबसे खूबसूरत पल यानी खेल, पढ़ाई और बचपन की जिज्ञासाओं से लबालब होते हैं। वे सब जलवायु आपदाओं, गरीबी और सामाजिक असमानताओं के दबाव में जल्दी ही विवाह की आग में झोंक दी जाती हैं।

गोसाबा द्वीप की गलियों में एक 14 वर्षीय लड़की, अजूं बागदीस, सुबह के अंधेरे में अपने छोटे-छोटे पैरों से खारे पानी में छलकते पानी को चीरते हुए भागती है, अपने साथ केवल कुछ कपड़ों का बंडल लिए हुए। सूरज की पहली किरणों से पहले ही वह अपनी जीवन यात्रा में उस मोड़ पर पहुंच चुकी होगी, जहां उसके बचपन को हमेशा के लिए त्याग दिया जाएगा। विवाह की रस्में साधारण होती हैं—कोई भव्य दावत नहीं, बस कुछ रिश्तेदार, उधार ली गई साड़ी और एक जीवन जिसे आजाद महसूस करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। यह जलवायु संकट की अदृश्य कीमत है, जिसे समाज और व्यवस्था ने लड़कियों की मासूमियत के रूप में वसूल लिया।

हालिया सर्वेक्षण इस संकट की गंभीरता को उजागर करते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 में पाया गया कि पश्चिम बंगाल में 20-24 वर्ष की उम्र की लगभग 42 प्रतिशत महिलाएं 18 वर्ष की उम्र से पहले ही विवाहिता हो चुकी थीं, जो राष्ट्रीय औसत 23.3 प्रतिशत का लगभग दोगुना है। सुंदरबन के द्वीपों में, गोसाबा ब्लॉक खासकर बाल विवाह के लिए चिन्हित है, जहां किशोरियों को घर का बोझ घटाने को विवाह करने को मजबूर किया जाता है। यहां के ग्रामीण रात में किए जाने वाले विवाहों की कहानियां फुसफुसाते हैं, जो अक्सर बिना पंजीकरण, अधिकारी की नजर से दूर, अनदेखी रह जाती हैं। यूनिसेफ के अनुमान के अनुसार, भारत के बाल विवाहों में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 13-15 प्रतिशत है, और इस डेल्टा के द्वीप-गोसाबा से लेकर बसंती, काकद्वीप और नामखाना तक—हर साल सैकड़ों किशोरियों को

विवाह के बंधन में बांधते हैं।

सरकारी हस्तक्षेप मौजूद हैं, लेकिन वे सतह तक ही सीमित हैं। साल 2023 में अधिकारियों ने दावा किया कि 1,500 बाल विवाहों को रोका गया और लगभग 900 एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि अधिकांश विवाह अब भी रिकॉर्ड में नहीं आते। इस क्षेत्र में बाल विवाह भूख, कर्ज व अनिश्चितता से निपटने की कठोर रणनीति है।

जलवायु परिवर्तन इस चक्र को और तेज करता है। पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्ययन से पता चलता है कि पिछले दशक में 55 प्रतिशत से अधिक घरों ने अंडरएज विवाहों में वृद्धि दर्ज की है। टेरेस डेस होमस के सर्वेक्षण में खुलासा हुआ कि पथर प्रतिमा और गोसाबा के 90 प्रतिशत लोग पिछले दस वर्षों में सीधे जलवायु आपदाओं का सामना कर चुके हैं, जिससे फसल उत्पादन और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई है। ऐसे क्षेत्र में किशोरियों की जल्दी शादी आर्थिक बचाव की रणनीति बन जाती है। प्रवास से जोखिम और बढ़ जाता है। केवल 17 प्रतिशत प्रवासी परिवार अपने साथ पति-पत्नी को ले जाते हैं और सिर्फ 7 प्रतिशत बच्चे को ले जाते हैं, जिससे नाबालिगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। रिपोर्टें बताती हैं कि बालिकाएं विवाह, जबरन श्रम, मानव तस्करी और विवाह प्रवासन से जुड़ी बढ़ती घटनाओं का सामना कर रही हैं।

मैदान के आंकड़े भले ही अधूरे हों, लेकिन परिणाम स्पष्ट हैं। लड़के परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ देते हैं; लड़कियां घरेलू श्रम, जल्दी गभर्धारण, स्वास्थ्य जोखिम और सीमित गतिशीलता के चक्र में फंस जाती हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक, 73.3 प्रतिशत विवाहित लड़कियां अन्य जिलों में पलायन करती हैं, अक्सर अजनबी समुदायों में, बिना यह सुनिश्चित किए कि उनके पति की मंशा या पृष्ठभूमि सुरक्षित भी है। गरीबी और सामाजिक हाशिए पर रहने वाले समुदाय इस संकट को और गहरा कर देते हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के घरों में 44 प्रतिशत बाल विवाह की दर दिखती है।

केनिंग के चिन्मय रे कहते हैं, ह्यकन्याश्री जैसी योजनाएं इन द्वीपों तक नहीं पहुंच पातीं। प्रशासनिक बाधाएं, कड़ा दस्तावेजीकरण, और राजनीतिक उपेक्षा हाशिए पर रहने वाले परिवारों को लाभ नहीं दिलातीं। प्रवर्तन की कमी बच्चों को असुरक्षित छोड़ देती है और पीड़ितों को मदद नहीं मिलती। टेरेस डेस होमस के सर्वेक्षण के अनुसार सुंदरबन की दो-तिहाई बालिकाएं अपनी शादी को पिछले आपदाओं से जोड़ती हैं। कोविड-19 लॉकडाउन ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया। स्कूल बंद होने से सुरक्षा की जगहें छिन गईं और बच्चे घरों में सीमित हो गए, जहां गरीबी, कर्ज और निराशा जीवित रहने की दिशा तय करती हैं। पठानखली गांव की 14 वर्षीय कल्याणी गेयन ने स्कूल छोड़ दिया, अपनी किताबें फटे कपड़े में बांधकर, क्योंकि उसकी मां फसल की विफलता के कर्ज चुकाने में संघर्ष कर रही थी। मधुपुर ढेला की 16 वर्षीय प्रिया जाना ने 2024 के तूफान में अपना घर खो दिया। खारे पानी ने खेतों को बर्बाद कर दिया। विकल्पों की कमी के कारण उसके माता-पिता ने उसके विवाह का निर्णय लिया।

स्कूल तटबंधों के साथ-साथ टूटते हैं। मौसुनी कोऑपरेटिव स्कूल, द्वीप का एकमात्र माध्यमिक विद्यालय, चिंता बढ़ाने वाली ड्रॉपआउट दर का गवाह है। प्रधानाध्यापक बिनय शि बताते हैं कि पिछले दो वर्षों में 14-18 वर्ष के लगभग 15-20 प्रतिशत छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं, तूफानों, गरीबी और जिम्मेदारियों के दबाव में।

मत्स्य और आजीविका विशेषज्ञ डॉ. अनिमेष राय कहते हैं, आय बढ़ी नहीं, नावें कम हैं, और बाल विवाह दरवाजे पर खड़ा है। बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर काले पानी में नाव से यात्रा करते हैं। कार्यकर्ता सर्मिष्ठा दत्ता गुप्ता कहती हैं, ह्यबाल विवाह कानून केवल कागजों पर है। लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 और 21 वर्ष है, लागू करना उन द्वीपों में विफल होता है, जहां सड़क की जगह नावें हैं और तूफान जीवन तय करते हैं। युवा दुल्हनें कई तरह के नुकसान झेलती हैं—उच्च जोखिम वाला गभर्धारण, एनीमिया, शिक्षा रुकना, मानसिक आघात और घरेलू बंदी। फिर भी, आशा की किरणें बची हैं। नूर स्कूल लौट गई; रूपा देवी स्वरोजगार समूह चलाती हैं; सालवीना ने दो बाल विवाह रोके; अंजलि पुलिस के साथ लड़कियों को बचाने में सहयोग करती हैं। उनका प्रतिरोध संस्थागत खामियों के बीच क्षमता की झलक दिखाता है। विशेषज्ञ जोर देते हैं कि प्रणालीगत समाधान जरूरी हैं-आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा, बिना बाधा वाली शिक्षा, आजीविका सुरक्षा, किशोर स्वास्थ्य सेवाएं और जवाबदेह प्रवर्तन।

सुदूर द्वीपों में बाल विवाह को परंपरा कहकर व्याख्यायित करना गलत है। सुंदरबन में, खारी मिट्टी, मुश्किल होता मछली पालन, टूटते तटबंध और बार-बार के चक्रवात आजीविका छीनते हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति में जल्दी विवाह जीवन रक्षा की रणनीति बन जाता है-आपदा से निपटने की एक हताश कोशिश। लेकिन हताशा नीति की जगह नहीं ले सकती। साक्ष्य बताते हैं कि जब वित्तीय प्रोत्साहन को निरंतर शिक्षा, किशोर स्वास्थ्य सेवाओं और सामुदायिक निगरानी से जोड़ा जाता है, तब बाल विवाह में कमी आती है।

विस्थापित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, दूरस्थ द्वीपों में कायर्शील माध्यमिक स्कूल, बाढ़ के दौरान स्वास्थ्य केंद्र, महिला प्रधान परिवारों के लिए रोजगार और मोबाइल प्रवर्तन तंत्र शामिल होना चाहिए। पर्यावरण नीति और लैंगिक न्याय में समन्वय बिना, हर तूफान प्रगति को मिटा सकता है।

अगर आपके पास हैं स्किल्स तो बिना डिग्री के नौकरी मिल सकती है

जब भी हम किसी जगह जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला सवाल यह होता है कि हमने किस विषय में डिग्री ली है । यह आम सी बात है कि अगर आपको किसी फील्ड में जॉब चाहिए, तो आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा दोनों में से कुछ न कुछ होना चाहिए, लेकिन कुछ नौकरियां ऐसी भी हैं, जिनमें डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास कम्यूनिकेशन, प्लानिंग, स्ट्रेटजी जैसे थोड़े से भी स्किल्स हैं तो बिना डिग्री के नौकरी मिल सकती है। आज हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में जिन्हें पाने के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं हैं।

सोशल मीडिया मैनेजर

सोशल मीडिया मैनेजर नए जमाने की क्रिएटिव जॉब है। एक सोशल मीडिया मैनेजर को ट्विटर, फेसबुक और लिंक्डइन जैसी साइट्स पर अपनी कंपनी का स्टेटस अपडेट लिखना, प्रमोशन कंटेंट बनाना, सवालों के जवाब देना और कमेंट्स का रिप्लाई करना जैसे काम करने होते हैं। अगर आपके भी क्रिएटिव हैं और लिखना पसंद करते हैं, तो ये जॉब के लिए बेस्ट साबित होगी।

कस्टमर सपोर्ट

अगर किसी भी कंपनी को बाजार में अपना प्रोडक्ट चलाना है तो इसके लिए कस्टमर को संतुष्ट करना सबसे जरूरी है। कस्टमर सपोर्ट एक ऐसा ही प्रोफेशन है जो कस्टमर्स का पूरा ख्याल रखने के लिए ही बना है। अगर आपके पास अच्छे कम्यूनिकेशन स्किल्स हैं तो आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं।

जूनियर डेवलपर

अगर टेक्निकल फील्ड में बिना डिग्री के करियर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप बतौर जूनियर डेवलपर जॉब कर सकते हैं। जूनियर डेवलपर्स उन वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के कोड बनाने में अहम योगदान अदा करते हैं, जिनका हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। एक जूनियर डेवलपर बनने के लिए आपको एचटीएमएल और सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, रूबी और पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंगवेज की समझ होनी चाहिए।

मोबाइल एप्प डिजाइनर

डिजाइनिंग का शौक रखने वाले लोग मोबाइल एप्प डिजाइनर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। इस नौकरी को पाने के लिए आपके पास डिजाइन प्रिंसिपल और पैटर्न्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। साथ ही विजुअल कम्यूनिकेशन स्किल्स भी होने चाहिए।

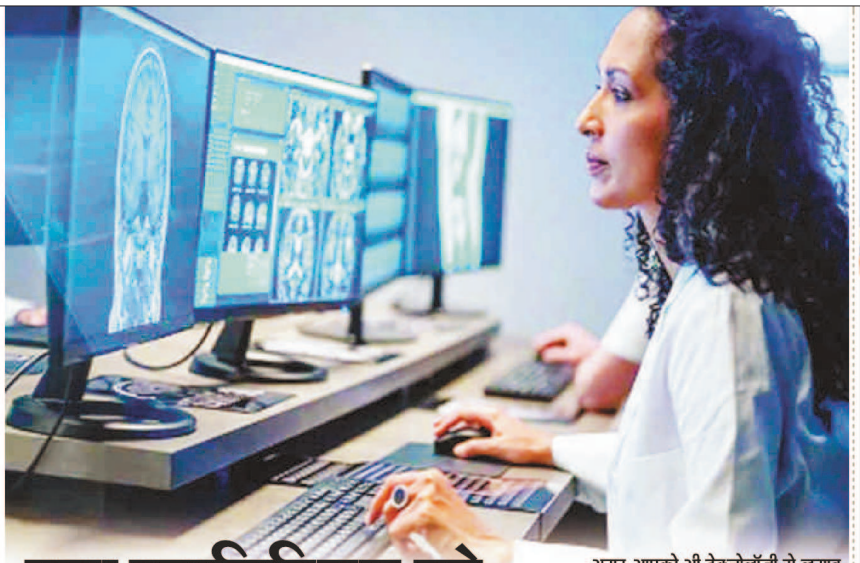

डाटा एनालिटिक्स को करियर के तौर पर चुनें
कर अच्छी कमाई सकते हैं

अगर आपको भी टेक्नोलॉजी से लगाव है और कोडिंग आदि में रुचि रखते हैं तो आप डाटा एनालिटिक्स को करियर के तौर पर चुन सकते हैं। आने वाले समय में इस कोर्स को लेकर काफी डिमांड भी बढ़ी है। इसमें आप अपना करियर बनाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं।

आजकल के दौर में डाटा एनालिटिक्स विषय महत्वपूर्ण कोर्सेज में से एक है। डाटा एनालिटिक्स कोर्स को ऑनलाइन भी किया जा सकता है। बता दें कि इस क्षेत्र में करियर संबंधी भी संभावनाएं भी काफी है। एक समय पर इन कोर्सों को करने के लिए स्टूडेंट्स को ऑफलाइन संस्थानों में जाना पड़ता था। लेकिन अब आप इन कोर्सेज को घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस कोर्स को टॉप संस्थानों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी पढ़ सकते हैं और वह एकदम फ्री में। ऑनलाइल कोर्स करने के लिए आपको किसी तरह की फीस नहीं देनी होती है।

हालांकि जब आप इस कोर्स को कम्प्लीट कर लेते हैं तो सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको रुपए देने होते हैं। ऐसे में अगर आप भी डाटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ फ्री कोर्स के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जिनकी मदद से आप डाटा एनालिटिक्स में अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं।

अप्लाइड बायेसियन फॉर एनालिटिक्स
संस्थान का नाम – आईआईएम बैंगलोर
कोर्स की फीस – फ्री
कोर्स की अवधि – 6 सप्ताह
सर्टिफिकेट की फीस – 11,974 रुपये

डाटा फॉर बेटर लाइफ – न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट
संस्थान का नाम – वर्ल्ड बैंक ग्रुप
कोर्स की फीस – फ्री
कोर्स की अवधि – 6 सप्ताह
सर्टिफिकेट की फीस – 388 रुपये

डाटा फॉर बेटर लाइफ – न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ पेस्ड
संस्थान का नाम – वर्ल्ड बैंक ग्रुप
कोर्स की फीस – फ्री
कोर्स की अवधि – 6 सप्ताह
सर्टिफिकेट की फीस – 388

इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिटिक्स फॉर मैनेजर
संस्थान का नाम – यूएम-एन आर्बर
कोर्स की फीस – फ्री
कोर्स की अवधि – 6 सप्ताह
सर्टिफिकेट की फीस – 3,987 रुपये

हरिकेन ट्रैकिंग विद सेटेलाइट डाटा
संस्थान का नाम – फ्यूचरलर्न के माध्यम से स्ट्रैथक्लाइड विश्वविद्यालय ग्लासगो
कोर्स की फीस – फ्री
कोर्स की अवधि– 5 सप्ताह
सर्टिफिकेट की फीस – 1,849 रुपये

डाटा एनालिटिक्स बेसिक फॉर एवरीवन
संस्थान का नाम – आईबीएम
कोर्स की फीस – फ्री
कोर्स की अवधि – 5 सप्ताह
सर्टिफिकेट की फीस – 7,541 रुपये

फंडामेंटल ऑफ टाइनीएमएल
संस्थान का नाम – हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी
कोर्स की फीस – फ्री
कोर्स की अवधि – 5 सप्ताह
सर्टिफिकेट की फीस – 16,203 रुपये

डाटा एनालिटिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस
संस्थान का नाम – हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, हांगकांग
कोर्स की फीस – फ्री
कोर्स की अवधि – 5 सप्ताह
सर्टिफिकेट की फीस – 7,683 रुपये

डाटा एनालिटिक्स फॉर लीन सिक्स सिगमा
संस्थान का नाम – कोर्सेरा के माध्यम से यूवीए एम्स्टर्डम
कोर्स की फीस – फ्री
कोर्स की अवधि – 5 सप्ताह
सर्टिफिकेट की फीस – 2,188 रुपये

डाटा एनालिटिक्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट
संस्थान का नाम – कोर्सेरा के माध्यम से सनी
कोर्स की फीस – फ्री
कोर्स की अवधि – 5 सप्ताह
सर्टिफिकेट की फीस – 2,188 रुपये

एनालिटिक्स फॉर डिजाइन मेकिंग
संस्थान का नाम – बाबसन कॉलेज,वेलेस्ले
कोर्स की फीस – फ्री
कोर्स की अवधि – 4 सप्ताह
सर्टिफिकेट की फीस – 18,887 रुपये

एजाइल एनालिटिक्स
संस्थान का नाम – यूवीए चार्लेट्सविले
कोर्स की फीस – फ्री
कोर्स की अवधि – 4 सप्ताह

डाटा एनालिटिक्स करियर गाइड एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन
संस्थान का नाम –आईबीएम
कोर्स की फीस – फ्री
कोर्स की अवधि – 4 सप्ताह
सर्टिफिकेट की फीस – उपलब्धता नहीं

गेटिंग स्टार्टड विद लेटर्स फॉर बिगनर्स ऑन एडब्ल्यूएस
संस्थान का नाम – अमेज़न वेब सेवाएं
कोर्स की फीस – फ्री
कोर्स की अवधि – 1 सप्ताह
सर्टिफिकेट की फीस – 3,806 रुपये

डाटा समार्ट फॉर बीगनर्स
संस्थान का नाम – जिगसाव अकादमी
कोर्स की फीस – फ्री
सर्टिफिकेट की फीस – उपलब्धता नहीं है

इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूर से न हों फ्रेंडली

कई बार ऐसा होता है कि रिटर्न एग्जाम क्लीयर करने के बाद किसी जॉब के लिए आपको चुन लिया जाता है और इंटरव्यूर आपको कहता है कि अब आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए आना है। जब भी कोई इंटरव्यूर आपसे ये बात कहता है, इसे सुनते ही आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता होगा, लेकिन फाइनल इंटरव्यू के लिए चुने जाने का ये मतलब नहीं है कि आपका सेलेक्शन पक्का हो गया है। हमेशा फाइनल इंटरव्यू को भी उतनी ही गंभीरता से लेना सीखें, जितना की इंटरव्यू के अन्य लेवल को लेते हैं। आज हम आपको बता रहे ऐसी बातों के बारे में जो आपको फाइनल इंटरव्यू के दौरान या उससे पहले कभी नहीं करनी चाहिए

ड्रेसिंग सेंस

जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, तो अपने ड्रेसिंग सेंस का विशेष रूप से ध्यान रखें। लोग अक्सर सोचते हैं कि फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाने का मतलब नौकरी पक्का होना होता है, लेकिन फाइनल इंटरव्यू के दौरान भी नियोक्ता आपको परखने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इसलिए फाइनल इंटरव्यू के लिए कभी कैजुअल ड्रेस में न जाएं और इंटरव्यू का ड्रेस कोड हमेशा फॉलो करें।

दोस्तों से न करें

उम्मीदवार फाइनल इंटरव्यू की बात सुनते ही पार्टी मोड में आ जाते हैं और बिना कोई समय गंवाए, अपने दोस्तों और करीबियों से अपने खुशी साझा करने लगते हैं। खुशी के पल दोस्तों के साथ साझा करना गलत बात नहीं है, लेकिन हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब तक काम पूरा न हो जाए, बात अपने तक ही रखी जाए। नियोक्ता कई बार फाइनल इंटरव्यू में आपके सामने ऐसे सवाल रखते हैं, जिनका जवाब आपके पास नहीं होता है और अवसर आपकी चौखट तक आने के बाद भी वापस लौट जाता है। इसलिए जब तक सेलेक्शन फाइनल न हो जाए पार्टी करने के बारे में न ही सोचें।

इंटरव्यूर से न हों फ्रेंडली

हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाए इस दौरान अनुशासन में रहें। कोई भी इंटरव्यूर आपका दोस्त नहीं होता है।अगर आप किसी इंटरव्यू को पहले से जानते भी हैं, तब भी इंटरव्यू के दौरान उसके साथ ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश न करें। फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने पर ज्यादातर उम्मीदवार कैजुअल बर्ताव करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका सेलेक्शन हो और आपको फाइनल इंटरव्यू में रिजेक्ट न किया जाए, तो इसके लिए कभी भी नियोक्ता से इस दौरान ज्यादा फ्रेंडली न हों और डेकोरम बनाए रखें।

नौकरी की तलाश में भटकते-भटकते परेशान हो चुके हैं? आज इस आर्टिकल से जरिए हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं। जिन्हें आप कम निवेश में करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।

कम निवेश में करके भी कमा सकते हैं ज्यादा मुनाफा

कई लोग नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटकते हैं। इसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। ऐसे में परेशान होने के बजाय आप खुद का बिजनेस शुरूकर हर महीने अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं। बता दें कि बिजनेश की शुरूआत करने के लिए आपको ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं होगी। इन बिजनेस को आप 2 से 5 लाख रुपए में शुरूकर सकते हैं। इन बिजनेस से आपकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी और आपकी नौकरी की तलाश भी खत्म हो जाएगी। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको इन बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं।

जिम या फिटनेस सेंटर

आज के दौर में हर व्यक्ति खुद को फिट और हेल्दी रखना चाहता है। वहीं बढ़ते पाल्यूशन और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक जागरूक होते जा रहे हैं। वहीं कई लोग खुद को फिट रखने के लिए जिम और योगा भी करते हैं। इसलिए अब न केवल मेट्रो शहरों बल्कि छोटे-छोटे शहरों में भी जिम या फिटनेस सेंटर की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि आप भी 5 लाख रुपए के निवेश से एक छोटा सा जिम शुरू कर सकते हैं। वहीं अधिक से अधिक लोगों के ज्वाइन करने पर आप इसका विस्तार भी कर सकते हैं।

डिस्पोजेबल पेपर प्लेट, कप, दोने बनाना

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शादियों, जन्मदिन समारोह और व्यावसायिक आयोजनों में लोगों द्वारा डिस्पोजेबल कप और प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इन चीजों की ऑफिस आदि में भी जरूरत होती है। वहीं लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। जिस कारण लोग प्लास्टिक प्लेट, कप, गिलास यूज करने की जगह पेपर से बनी इन चीजों का इस्तेमाल करना अधिक पसंद करते हैं। ऐसे में आप भी इस बिजनेस को आसानी से शुरूकर सकते हैं। इनको बनाने वाली मशीनें आपको 5 लाख से कम के निवेश में एक मशीन आसानी से मिल जाएंगी।

पेस्ट कंट्रोल बिजनेस

अधिकतर घरों में तिलचट्टे, उड़ने वाले कीड़े और अन्य कीड़े पाए जाते हैं। यही कीड़े फसलों और सब्जियों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए कीड़ों से बचाव के लिए लोग पेस्ट कण्ट्रोल सेवाओं की खोज करते हैं। ऐसे में बहुत से लोग उपकरण और कीटनाशकों का उपाय खोजते हैं। जो इन कीड़ों और चूहों आदि के नुकसान से बचा सके। कीटों को खत्म करने के संसाधनों और रासायनिक स्प्रे में निवेश कर सकते हैं। इस दौरान रेस्तरां, पब, कॉर्पोरेट कार्यालय, फर्म्स, होटल, हाउसिंग सोसाइटी और अन्य आपके उपभोक्ता हो सकते हैं। इस बिजनेस को भी आप 5 लाख के निवेश से शुरू कर सकते हैं।

फोटो स्टूडियो सर्विसेज

फोटोग्राफी के स्टाइल में पहले से काफी चेंज आया है। आजकल लोग शादी, बच्चों, प्री-वेडिंग, प्रेग्नेंसी शूट, जन्मदिन आदि की अच्छी फोटोग्राफी करवाते हैं। वहीं कुछ लोग हर पल को कैमरे में कैद करना चाहते हैं। इसके लिए लोग पैसै भी खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए फोटोग्राफी के बिजनेस में आप हाथ आजमा सकते हैं। हालांकि इस काम को शुरू करने के लिए आपके पास पेशेवर कौशल का होना काफी जरूरी है। अगर आपको भी यूनिक तरीके से फोटो क्लिक करने का शौक है तो आप इस फील्ड में अपनी शुरूआत कर सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

बता दें कि किसी भी क्षेत्र में अपना काम शुरू करने से पहले उस पेशे की सारी डिटेल्स होना जरूरी है। जिस भी काम को आप शुरू करने जा रहे हैं। उसे कैसे करते हैं, आगे कैसे बढ़ाते है इन सबकी बारीक जानकारी होने के बाद ही आप किसी भी काम को करें। क्योंकि अगर आपको अपने काम की नॉलेज नहीं होगी तो आप ज्यादा समय तक किसी भी फील्ड में अपने पांव नहीं टिका कर रख सकते हैं। कॉम्पटीशन के दौर में कुछ अलग और हटके काम करना आपको एक अलग पहचान देता है।

जब शबाना रजा बनीं 'नेहा'

एकनाम ने बदल दी पहचान और बना दिया खास चेहरा

फिल्मी दुनिया में नाम का बेहद महत्व होता है। कई बार एक नाम ही किसी कलाकार की पूरी पहचान बन जाता है और उसे लोगों के दिलों में खास जगह दिलाता है। ऐसी ही एक कहानी है अभिनेत्री शबाना रजा की, जिन्हें आज भी लोग 'नेहा' के नाम से याद करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह नाम उन्हें फिल्मों में आने के बाद मिला और धीरे-धीरे यही उनकी असली पहचान बन गया।

शबाना रजा का जन्म 18 अप्रैल 1975 को हुआ था। वह एक साधारण परिवार से थीं, उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की। वह कभी फिल्मों में नहीं आना चाहती थीं, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिसे उन्होंने पहले तो ठुकरा दिया, लेकिन बाद में परिवार के समझाने पर उन्होंने हां कह दी। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब उन्होंने साल 1998 में फिल्म 'करीब' से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म के निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा थे। इसी फिल्म में उनके किरदार का नाम 'नेहा' था और निर्देशक ने उन्हें यही नाम अपनाने की सलाह दी। धीरे-धीरे यह नाम इतना लोकप्रिय हो गया कि शबाना रजा को लोग उनके असली से ज्यादा 'नेहा' के नाम से जानने लगे। फिल्म 'करीब' में उनके साथ बॉबी देओल नजर आए थे। इस फिल्म में उनकी सादगी और मासूमियत को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद, नेहा ने 'होगी प्यार की जीत' में अजय देवगन के साथ काम किया। यह फिल्म सफल रही और इससे उनकी पहचान और मजबूत हुई। उन्होंने 'फिजा' में ऋतिक रोशन के साथ भी काम किया। इसके अलावा, 'राहुल' और 'आत्मा' समेत कई फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों को दीवाना बनाया। हालांकि, उनका करियर ज्यादा समय तक नहीं रहा। धीरे-धीरे उन्होंने फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी और आखिरकार साल 2009 में 'एसिड फैक्ट्री' के बाद वह पूरी तरह से पर्दे से दूर हो गईं। निजी जिंदगी की बात करें तो, शबाना रजा ने मनोज बाजपेयी से 2006 में शादी की। दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई। कई सालों तक एक-दूसरे को समझने के बाद उन्होंने शादी के बंधन में बंधने का फैसला लिया। शादी के बाद नेहा ने अपने परिवार को प्राथमिकता दी और फिल्मों से दूरी बना ली।

मां के लिए जरीन खान का छलका दर्द, नोट शेयर कर लिखा, 'आप के बिना सब खाली है'

अभिनेत्री जरीन खान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कुछ दिन पहले उनकी मां परवीन खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। शुक्रवार को अभिनेत्री ने अपनी मां के लिए खास पोस्ट किया। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां के साथ पुरानी यादों का मोंटाज वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में जरीन और उनकी मां साथ में हंसती-खेलती नजर आ रही हैं। जरीन ने पोस्ट में लिखा, 'निश्चय ही हम ऊपरवाले के हैं और एक दिन हमें वहीं जाना है। मां, आपको गए हुए अभी बस 10 दिन हुए हैं। मैं दुनिया के लिए कोई बड़ा कैप्शन नहीं लिखूंगी, क्योंकि आप पहले से ही जानती हैं कि मैं अभी क्या महसूस कर रही हूं। '

उन्होंने आगे लिखा, 'मेरे दिल में एक दर्द और खालीपन है, जिसे कोई भी भर नहीं सकता। आप हमेशा सही रहें और ऊपर अच्छे से रहें, जब तक हम फिर से नहीं मिलते हैं। ' अभिनेत्री जरीन खान की मां लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं। अक्टूबर 2025 में भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभिनेत्री ने मां के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था और लगातार अपडेट दे रही थीं। इसके साथ ही, फैंस से उनकी जल्दी ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ करने की अपील कर रही थीं। जरीन खान अपनी मां के बहुत करीब थीं और अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती थीं। जरीन खान ने 2010 में सलमान खान के साथ फिल्म 'वीर' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। कटरीना कैफ से समानता के कारण चर्चा में आई जरीन ने 'हाउसफुल 2', 'हेट स्टोरी 3' और 'अक्सर 2' जैसी फिल्मों में अभिनय किया।

समय जल्दी बीत जाता है...

अमिताभ बच्चन ने क्यों कही ये बात? पिता हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का किया जिक्र

सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में भी फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया और ब्लॉग पर भी लगातार सक्रिय हैं। वो अक्सर अपने ब्लॉग्स के जरिए भी लोगों को प्रेरित करते रहते हैं और प्रेरणादायक बातें साझा करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने ब्लॉग पोस्ट में सक्रिय और प्रेरित रहने के महत्व पर विचार व्यक्त किया। इसके लिए उन्होंने अपने पिता व रचनाकार हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियों का भी जिक्र किया।

शरीर को गतिशील रखें

अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं से प्रेरणा लेते हुए अमिताभ ने समय की अस्थिरता और शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्रिय रहने के महत्व के बारे में बात की। अपने ब्लॉग में उन्होंने लिखा, 'बाबूजी की रचनाओं से कुछ विचार और दिन बीतते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बीता था और अगला महीना शुरू होने वाला है। यह हमें याद दिलाता है कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है। गतिशीलता ही कुंजी है। शरीर को गतिशील रखें, मन को गतिशील रखें और गतिशीलता की शक्ति अचानक स्पष्ट हो जाएगी, न कि बिना किसी कारण के बैठे रहने से।'

धैर्य और ज्ञान का बताया महत्व

बिग बी ने धैर्य और ज्ञान के महत्व पर भी बात की। उन्होंने लिखा, 'धैर्य उस पहेली की तरह है, जिसका हल हर पल चाहिए। एक पल भी धैर्य की परीक्षा है। आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि दार्शनिक दृष्टि से।' उन्होंने ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, 'किसी भी विषय का अध्ययन युद्ध के संदर्भ में धनुष से कई तीर निकालने जैसा है।

200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस:

सरकारी गवाह बनना चाहती हैं जैकलीन , कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक नया और बड़ा मोड़ सामने आया है। लंबे समय से चल रहे इस हाई-प्रोफाइल केस में अब जैकलीन ने खुद आगे आकर सरकारी गवाह (अप्रूवर) बनने की इच्छा जताई है। दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जैकलीन फर्नांडिस ने कहा कि वह इस मामले में जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना चाहती हैं और सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार हैं। इस पर अदालत ने बताया कि इसके लिए उन्हें सीधे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने औपचारिक आवेदन देना होगा। कोर्ट ने साफ किया कि जांच एजेंसी उनके बयान और सहयोग के आधार पर ही तय करेगी कि उन्हें अप्रूवर बनाया जाए या नहीं। अदालत ने इस मामले में ईडी को नोटिस भी जारी किया है और अगली सुनवाई की तारीख 20 अप्रैल तय की है।

इसके अलावा, जैकलीन को 24 अप्रैल से 25 मई के बीच विदेश यात्रा की अनुमति भी दे दी गई है। हालांकि, इस दौरान उन्हें तय शर्तों का पालन करना होगा और जांच में सहयोग जारी रखना होगा। बता दें कि पूरा मामला 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर को मुख्य आरोपी माना गया है। आरोप है कि उसने जेल के अंदर रहते हुए ही ठगी और रंगदारी का बड़ा नेटवर्क चलाया और कई लोगों से करोड़ों रुपए वसूले। इसी दौरान उसका संपर्क बॉलीवुड से भी जुड़ा, और जैकलीन फर्नांडिस का नाम इस केस में सामने आया। ईडी की जांच के मुताबिक, सुकेश ने जैकलीन को कई महंगे तोहफे दिए थे, जिनमें लग्जरी घड़ियां, महंगे बैग, ज्वलरी और अन्य कीमती सामान शामिल हैं। एजेंसी का दावा है कि ये सभी चीजें गैरकानूनी तरीके से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थीं। हालांकि, इस पर जैकलीन का कहना है कि उन्हें सुकेश की असली पहचान और उसके अपराधों के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने अदालत को बताया कि सुकेश ने खुद को एक बड़ा बिजनेसमैन बताकर उन्हें गुमराह किया था।

मां बनने के बाद बढ़ते वजन पर ट्रोल करने वालों को भड़कीं पत्रलेखा

सोशल मीडिया की दुनिया जितनी तेज और चमकदार दिखती है, उतनी ही तनावपूर्ण भी होती है। खासकर फिल्मी सितारों के लिए यह दबाव और भी बढ़ जाता है, जहां हर बदलाव के साथ यूजर्स के कमेंट्स से गुजरना पड़ता है। इस कड़ी में अभिनेत्री पत्रलेखा को भी ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मां बनने के बाद उनके बढ़ते वजन को लेकर लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। इस पर पत्रलेखा ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। पत्रलेखा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें अभिनेत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है और यह उनके शरीर में आए बदलाव का सबसे बड़ा कारण है। पत्रलेखा ने उन लोगों को निशाने पर लिया, जो लगातार उनके बढ़ते हुए वजन पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ''मुझे क्या हुआ है, इसका जवाब यही है कि मैंने अभी-अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। यह बदलाव पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लोगों को ऐसा लगता है जैसे मैंने जरूरत से ज्यादा खा लिया हो, जबकि सच्चाई यह है कि मैंने इस दौरान एक नई जिंदगी को जन्म दिया है।'' पत्रलेखा ने कहा, ''प्रेग्नेंसी के दौरान और उसके बाद शरीर में बदलाव आना पूरी तरह सामान्य बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग बिना समझे तुरंत कमेंट कर देते हैं। मैंने पहाड़ नहीं खाया है, बल्कि एक बच्चे को जन्म दिया है। मैं अपनी मातृत्व की जिम्मेदारी निभा रही हूं और साथ ही दो फिल्मों के निर्माण का काम भी संभाल रही हूं, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। अपने पोस्ट के आखिर में पत्रलेखा ने लोगों से भावनात्मक अपील की और कहा, ''अगर मेरे हाथ में होता तो मेरा शरीर ऐसा न होता, लेकिन यह पूरी तरह शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। मेरी लोगों से आग्रह किया कि किसी भी महिला के शरीर पर कमेंट करने से पहले उसके हालात और संघर्ष को समझने की कोशिश करें। हर किसी को थोड़ा तो दयालु बनना चाहिए। पत्रलेखा और अभिनेता राजकुमार राव ने पिछले साल 15 नवंबर को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था। कपल ने अपनी बेटी का नाम पार्वती पॉल राव रखा।

युजवेंद्र चहल के 'मैसेज' विवाद पर तान्या चटर्जी ने तोड़ी चुप्पी

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल इन दिनों मैदान से ज्यादा सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इंफ्लुएंसर तान्या चटर्जी ने दावा किया था कि चहल ने उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था। इस छोटे से मैसेज ने देखते ही देखते बड़ा विवाद खड़ा कर दिया और इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। इंफ्लुएंसर ने आईएएनएस के साथ बातचीत में इस विषय पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'वह बस एक सामान्य मैसेज था। इसमें कोई बुराई या फिर विवाद छेड़ने जैसा कुछ भी नहीं था। मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं। वे एक भारतीय खिलाड़ी हैं और देश के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने मुझे सिर्फ 'क्यूट' कहा था और आईपीएल के बारे में बातचीत चल रही थी।' तान्या ने आगे बताया कि पूरी बातचीत के दौरान चहल से जुड़ा टॉपिक सामने आया और उन्होंने इसे ऐसे ही बता दिया। उन्होंने कहा, 'मेरा इरादा चहल को बदनाम करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इसी तरह रहती हूं। मुझमें वह मासूमियत अभी भी है। मेरे अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा और हमेशा बरकरार रहेगा। उन्होंने मेरी तारीफ की थी, मुझे अच्छा लगा, बात खत्म। '

अभिनेत्री ने आगे कहा, 'मैं समझ नहीं पा रही हूं कि मानहानि का केस कैसे हो सकता है। मैंने तो उन्हें बदनाम नहीं किया, बल्कि, उनकी तारीफ ही की थी। ' उन्होंने कहा, 'चहल एक भारतीय क्रिकेटर हैं और आईपीएल में खेल रहे हैं। मैं उनकी निजी जिंदगी में दखल नहीं दे रही हूं और न ही किसी और चीज में। यह बस एक तारीफ थी, जिसे मैंने अपनी मासूमियत से सभी के सामने शेयर किया। ' तान्या ने अपनी बात को साफ करते हुए कहा कि यह घटना 2023 की है। अगर उन्हें कुछ ऐसा करना होता, तो वे पहले ही कर देती। यह 2023 में हुआ था। सबको पता था कि उस समय वह शादीशुदा थे। उन्होंने मुझे मैसेज किया था, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। मुझे यह देर से पता चला। लेकिन अगर मैं उस समय किसी पीआर या ऐसी ही किसी टीम के साथ जुड़ी होती, तो शायद मुझे पता चल जाता। मेरा कोई पीआर नहीं है। इंफ्लुएंसर ने कहा कि मेरे वकील इस मामले को देख रहे हैं और उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ कहने से मना किया है, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि उन्होंने ही मुझे मैसेज किया था। वह एक प्यारा सा मैसेज था और एक बार नहीं, दो बार किया था।

अगले साल स्लीज होगी 'लव एंड वॉर', भंसाली की प्रेम कहानी में दिखेंगे रणबीर, आलिया और विक्की कौशल

बॉलीवुड में जब भी बड़े पैमाने की फिल्मों की बात होती है, तो संजय लीला भंसाली का नाम अपने आप सामने आ जाता है। अब एक बार फिर वह दर्शकों के लिए एक बड़ी और खास फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है 'लव एंड वॉर'... इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफी चर्चा हो रही है। इसकी रिलीज डेट सामने आने के बाद दर्शकों का उत्साह और बढ़ गया है। फिल्म की स्टार कास्ट काफी दमदार है। इसमें रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट जैसे बड़े कलाकार नजर आएंगे। इस बीच मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है। दरअसल, मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा कर इसकी रिलीज डेट की घोषणा की।

इस तस्वीर में संजय लीला भंसाली के साथ रणबीर, विक्की और आलिया नजर आ रहे है। मेकर्स ने बताया कि यह फिल्म अगले साल गणतंत्र दिवस से पहले आएगी। यह फिल्म 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 'लव एंड वॉर' एक प्रेम कहानी है। साथ ही इसमें भावनाओं और संघर्ष से भरे सीन्स भी देखने को मिलेंगे। यह फिल्म खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें भंसाली पहली बार विक्की कौशल के साथ काम कर रहे हैं। वहीं, रणबीर कपूर के साथ उनकी ये दूसरी फिल्म है, इससे पहले वह फिल्म 'सांवरिया' में उनके साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा, आलिया भट्ट के साथ वह 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के बाद फिर से काम कर रहे हैं। 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट को लेकर चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उसी समय कुछ और बड़ी फिल्मों के आने की संभावना है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया मावा मोदोल लाइब्रेरी चारामा का शुभारंभ

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रविवार को कांकेर जिले के चारामा में मावा मोदोल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। लोकार्पण पश्चात उन्होंने लाईब्रेरी का अवलोकन कर वहां अध्ययनरत युवाओं से संवाद किया तथा उनसे अपने विद्यार्थी जीवन को साझा करते हुए कहा कि लगन से पढ़ाई करें, सरकार जो सुविधाएं उपलब्ध करा रहीं है, उसका लाभ उठाए और सफल होकर अपने देश-प्रदेश व क्षेत्र का नाम रौशन करें। देश के प्रति हमेशा निष्ठावान रहें।

उन्होंने सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। कुल 43 लाख रूपए की लागत से निर्मित इस सवर्सुविधायुक्त लाईब्रेरी में एक साथ 75 विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत तथा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण नरेटी विशेष रूप से उपस्थित थी।

लाईब्रेरी के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लगातार बच्चों के भविष्य को गढ़ने का कार्य किया जा रहा है। चाहे दिल्ली मे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना हो, अथवा प्रदेश में लाईब्रेरी व नालंदा परिसरों की स्थापना, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समूचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कांकेर जिले में भी जिला प्रशासन द्वारा लगातार बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, इसी कड़ी में आज मावा मोदोल लाईब्रेरी चारामा का शुभारंभ हो रहा है। पूरे क्षेत्र के बच्चे यहां अच्छे वातावरण में पढ़ाई कर अपना भविष्य गढ़ सकते हैं। उन्होंने क्षेत्रवासियों सहित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी युवाओं एवं उनके पालकों को अपनी शुभकामनाएं भी दी।

समारोह को स्थानीय विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मावा मोदोल लाइब्रेरी की स्थापना से इस क्षेत्र के बच्चों को लाइब्रेरी का लाभ मिलेगा। मावा मोदोल लाईब्रेरी में अच्छी तैयारी कर बच्चे अपना भविष्य संवार सकते हैं। कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसार ने अपने उद्बोधन में बताया कि जिले के सभी 11 तहसील मुख्यालय में मावा मोदोल लाईब्रेरी की स्थापना की जाएगी, ताकि उस क्षेत्र के बच्चे लाईब्रेरी में पढ़ाई कर उच्च पदों पर आसीन हो सके। कांकेर जिले का यह छंटवा लाईब्रेरी है, इससे पूर्व कांकेर, भानुप्रतापपुर, कोरर, दुर्गूकोंदल और अंतागढ़ में मावा मोदोल निःशुल्क लाईब्रेरी संचालित की जा रही है।

कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद कांकेर के अध्यक्ष अरुण कौशिक, नगर पंचायत चारामा के अक्ष्यक्ष भुनेश्वर नाग, पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा, सीईओ जिला पंचायत हरेश मंडावी, जिला शिक्षा अधिकारी रमेश निषाद, महेश जैन, उमादेवी शर्मा सहित गणमान्य नागरिक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर विद्यार्थी एवं शिक्षकगण उपस्थित थे।

खास खबर

मुख्यमंत्री साय की पहल से प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को मिलेगी मजबूती, जशपुर सहित कई क्षेत्रों को बड़ी सौगात

रायपुर। प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ और विश्वसनीय बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जशपुर जिले सहित राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए व्यापक योजना लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जशपुर जिले के 133 गांवों, नगरों और टोला-मुहल्लों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे। इस पहल से लंबे समय से चली आ रही लो वोल्टेज और बार-बार बिजली बाधित होने की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा। इससे किसानों, छात्रों और लघु व्यवसायियों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी दैनिक गतिविधियां अधिक सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी।

प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत अधोसंरचना के विस्तार के तहत जशपुर जिले में उच्च स्तरीय परियोजनाओं पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। कुनकुरी के हर्राडांड में 400/220 केवी का अत्याधुनिक उपकेंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो राज्य के प्रमुख उच्च क्षमता उपकेंद्रों में शामिल होगा। इसके अतिरिक्त सलिहाटोली, विपतपुर, भगोरा, समडमा, मैनी, रेड़े, पालीडीह, खुटेरा एवं चेटवा सहित विभिन्न स्थानों पर नए 33/11 केवी सब-स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। साथ ही फरसाबहार और झिक्की बगीचा में 132/33 केवी के उच्च क्षमता सब-स्टेशन भी स्वीकृत किए गए हैं, जिससे क्षेत्रीय विद्युत वितरण प्रणाली और अधिक सशक्त होगी।

इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में व्यापक सुधार आएगा, लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या में कमी आएगी तथा औद्योगिक और कृषि गतिविधियों को नई गति मिलेगी। राज्य सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। प्रदेशवासियों ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

किसानों को समर्थन मूल्य से किया जा रहा है वंचित : चोवाराम साहू

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

छत्तीसगढ़ साहू समाज के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चोवाराम साहू ने कबीरधाम जिले में दलहनी-तिलहनी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत 15 फरवरी 2026 से खरीफ एवं रबी दलहनी-तिलहनी फसलों की खरीदी शुरू करने की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है।

उन्होंने बताया कि जिले के चारों विकासखंड- कवर्धा, पंडरिया, स. लोहारा और बोड़ला में करीब 66 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसानों को अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों जैसी अधिसूचित फसलों को समर्थन मूल्य पर बेचने की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि अधिकांश केंद्रों में खरीदी सुचारू रूप से नहीं हो रही है। चोवाराम साहू के अनुसार, किसानों को मजबूरी में अपनी उपज व्यापारियों को औने-पौने दामों में बेचनी पड़ रही है। रबी की प्रमुख फसल चना, जिसकी कटाई और मिसाई लगभग पूरी हो चुकी है, वतर्मान में मंडी में 5000 से 5300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रही है, जबकि शासन द्वारा इसका समर्थन मूल्य 5875 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापारियों की सांठगांठ के चलते मंडी में कीमतें कृत्रिम रूप से नीचे रखी जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उपार्जन केंद्रों में किसानों को तरह-तरह के बहाने बनाकर लौटा दिया जा रहा है। कहीं सर्वर डाउन होने तो कहीं पोर्टल नहीं खुलने का हवाला दिया जा रहा है। हाल ही में किसानों द्वारा आवाज उठाए जाने पर जिले कुछ केन्द्रों में खरीदी शुरू की गई है लेकिन अधिकांश केन्द्रों में खरीदी अभी भी बंद है। किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष साहू ने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन फसलों का समर्थन मूल्य और बाजार भाव दोनों ही किसानों के हित में नहीं हैं। चना सहित अन्य फसलों के दाम कई वर्षों से लगभग स्थिर हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

प्रदेश सरकार की सकारात्मक व विकासपरक सोच से जिले में हो रहे नवाचार : अरुण साव

उप मुख्यमंत्री ने वित्तीय साक्षरता लैब और कोया बाना आदिवासी संस्कृति संवर्धन संस्थान का किया लोकार्पण

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल और युवा कल्याण तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने आज जिला मुख्यालय कांकेर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर निर्माण कार्यो का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कोमलदेव शासकीय जिला चिकित्सालय परिसर में ट्रामा सेंटर तथा ओपीडी एवं अतिरिक्त भवन निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इसके अलावा पुत्री शाला परिसर का जीणीद्धार कर वित्तीय साक्षरता लैब और कचहरी परिसर स्थित मावा मोदोल कोचिंग संस्थान प्रांगण में कोया बाना आदिवासी संस्कृति संवर्धन संस्थान का भी लोकार्पण जिले के प्रभारी मंत्री श्री साव ने किया।

कोया बाना आदिवासी संस्कृति संग्रहालय के लोकार्पण पश्चात नगरवासियों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि कांकेर जिले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा क्योंकि यहां कुल 11 करोड़ 21 लाख रूपए के विभिन्न निर्माण कार्यो और नवाचारों का लोकार्पण हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की सकारात्मक और विकासपरक सोच ही परिणाम है कि जिले में इतनी तादाद में विकास की झलकियां देखने को मिल रही हैं। वहीं आने वाली पीढ़ी को आदिवासी संस्कृति और विरासत को करीब से जानने के लिए कोया बाना जैसे बहुउद्देशीय संग्रहालय का आज लोकार्पण हुआ। श्री साव ने कहा कि कांकेर जिले को सहेजने और संवारने का काम शासन, प्रशासन और जिले के जनप्रतिनिधि के द्वारा परस्पर समन्वय के साथ किया जा रहा है। उन्होंने नगरवासियों को इन संस्थानों का लाभ उठाने की अपील की।

विशिष्ट अतिथि की आसंदी से कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्री साव के नेतृत्व में कांकेर जिले को लगातार सौगातें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार की इच्छाशक्ति से बस्तर के नक्सलमुक्त होने के बाद अब यहां सतत विकास देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सरकारें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यहां की आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक विरासतों को संजोने व संवर्धन करने हर संभव प्रयासरत है, जिसका उदाहरण कोया बाना संग्रहालय है जो युवाओं को उनकी प्राचीन परंपरा और सभ्यता से अवगत कराएगा। कार्यक्रम के अंत में उप मुख्यमंत्री एवं अन्य मंचस्थ अतिथियों ने मासिक पत्रिका नवांकुर और हल्बा जनजाति की लोक संस्कृति नामक पुस्तिका का विमोचन किया। विदित हो कि कोया बाना आदिवासी संस्कृति संवर्धन संस्थान में गोड़ी पाठशाला का संचालन और सांस्कृतिक लाइब्रेरी की स्थापना, आदिवासी पुरातत्व संग्रहालय एवं युवाओं के लिए रेडियो स्टूडियो की स्थापना की गई है। उक्त संस्थान की स्थापना जिला खनिज न्यास निधि मद से 30 लाख रूपए की लागत से की गई है।

ट्रामा सेंटर और अतिरिक्त अस्पताल भवन का किया लोकार्पण

इसके पहले उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कोमलदेव शासकीय जिला चिकित्सालय में आधुनिक तकनीक से लैस ट्रामा सेंटर और ओपीडी एवं अतिरिक्त अस्पताल भवन का लोकार्पण किया। उक्त ट्रामा सेंटर की स्थापना 01 करोड़ 41 लाख 35 हजार रूपए की लागत से डीएचएस एवं डीएमएफ मद से की गई है, जहां गंभीर मरीजों का उपचार उन्नत चिकित्सा पद्धति से तात्कालिक रूप से हो सकेगा। इसी तरह डीएमएफ मद से 08 करोड़ 42 लाख रूपए की लागत से ओपीडी एवं अतिरिक्त अस्पताल भवन का भी लोकार्पण उप मुख्यमंत्री श्री साव के द्वारा किया गया। इन चिकित्सा अधोसंरचनाओं के निर्माण से मरीजों को विभिन्न सेवाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इस दौरान उन्होंने ट्रॉमा यूनिट में भर्ती मरीजों व उनके परिजनों से बातचीत कर हालचाल जाना।

वित्तीय साक्षरता लैब में बच्चे खेल-खेल में बनेंगे जागरूक उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री साव ने कांकेर प्रवास के दौरान आज पोस्ट ऑफिस के समीप पुराने पुत्रीशाला परिसर में वित्तीय साक्षरता लैब का लोकार्पण किया। उक्त लैब का निर्माण पुराने शाला भवन का जीणीद्धार कर किया गया है। डीएमएफ मद से कुल 65 लाख रूपए की लागत से उक्त लैब का निर्माण आधुनिकीकृत ढंग से किया गया है, जहां पर विद्याथिर्यो एवं आम नागरिकों को वित्तीय सशक्तिकरण, सायबर फ्रॉड के प्रति जागरूकता तथा व्यावसायिक निवेश कंपनी अधिनियम की जानकारी, जीएसटी, टीडीएस एवं कर प्रणाली की समझ और शेयर मार्केट से परिचय व शासन की योजना एवं आर्थिक बजट की जानकारी सहित बैंकिंग प्रणाली और निवेश आदि की वित्तीय जानकारी मिलेगी।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत, नगर पालिका कांकेर के अध्यक्ष अरूण कौशिक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण नरेटी, उपाध्यक्ष श्रीमती तारा ठाकुर, कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा, जिला पंचायत सीईओ हरेश मण्डावी, पूर्व विधायक श्रीमती सुमित्रा मारकोले सहित नागरिक महेश जैन, दिलीप जायसवाल एवं नगर के पार्षद, जनप्रतिनिधिगण एवं नागरिक उपस्थित थे।

माओवाद के बाद विकास की एक नई राह : पुसपाल बनेगा ईको-टूरिज्म हब

रिसॉर्ट और ओपन रेस्टोरेंट से बढ़ेगा पर्यटन और आजीविका के साधन : मंत्री केदार कश्यप

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

कोण्डागांव जिले के पुसपाल क्षेत्र से माओवाद खत्म होने के बाद अब विकास की नई तस्वीर उभर रही है। वर्षो तक प्रभावित रहने के कारण जहां पर्यटन गतिविधियां ठप थीं, वहीं अब केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र में शांति स्थापित हुई है और पर्यटन की संभावनाएं फिर से जीवंत हो गई हैं।

इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने ग्राम परौदा में लगभग एक करोड़ 45 लाख 96 हजार रूपए की लागत से बनने वाले ईको-टूरिज्म रिसॉर्ट का भूमिपूजन किया। इसके साथ ही पुसपाल क्षेत्र में ही एक करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से नदी तट पर बनने वाले ओपन रेस्टोरेंट का भी भूमिपूजन किया।

वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि पुसपाल को विकसित करने का उद्देश्य कोण्डागांवझबस्तर ईको-टूरिज्म सर्किट को मजबूत बनाना है। अभी तक पर्यटक टाटामारी और चित्रकूट तक ही सीमित रहते थे, लेकिन अब पुसपाल में नई गतिविधियां शुरू होने से पर्यटन का दायरा भी बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि यहां भंवरडीह नदी में एटीवी राइड, एडवेंचर स्पोर्ट्स, रिवर राफ्टिंग और बांस राफ्टिंग जैसी गतिविधियां शुरू की जाएंगी।

साथ ही पुसपाल वैली में व्यू पॉइंट से सूर्यास्त का अद्भुत नजारा देखने के साथ पर्यटक ईको-कॉटेज में रात्रि में सितारों से भरे आकाश का आनंद लेते हुए विश्राम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ईको-टूरिज्म के विकास से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और क्षेत्र की संस्कृति को देश-विदेश में पहचान मिलेगी।

कार्यक्रम के दौरान तेंदूपत्ता संग्राहकों को संग्रहण कार्ड भी वितरित किए गए। मंत्री श्री कश्यप ने संग्राहकों से अपील की कि वे अधिक मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता का तेंदूपत्ता संग्रह करें, ताकि उन्हें बेहतर मूल्य और बोनस का लाभ मिल सके।

अंत में वन विभाग ने सभी जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से वनों को आग से बचाने, उनकी सुरक्षा करने और अवैध अतिक्रमण रोकने में सहयोग की अपील की। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती यशोदा कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति रही।

विधायक ने नीति आयोग मद से ग्राम मथनीबेड़ा में 'अस्मिता परियोजना' का किया शुभारंभ

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

आदिवासी बहुल कोंडागांव जिले के ग्राम मथनीबेड़ा में शुक्रवार की शाम बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक सुश्री लता उसेंडी द्वारा नीति आयोग मद से महत्वाकांक्षी पहल अस्मिता परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीता शोरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

विधायक ने कहा कि गांव के हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यह काययोजना बनाई गई है। ह्वअस्मिता परियोजनाह्व का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि स्वतंत्र एवं सफल उद्यमी के रूप में स्थापित करना है। इस पहल के माध्यम से महिलाओं को व्यक्तिगत पोल्ट्री शेड प्रदान कर स्थायी एवं दीघर्कालिक स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। परियोजना के तहत महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ समाज में सम्मानजनक पहचान दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही गांव को पक्की सड़क की सुविधाएं मिलेगी और सरकार के मंशानुरूप गांव में सभी आवश्यक मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

कलेक्टर ने कहा कि अस्मिता प्रोजेक्ट के तहत पायलट प्रोजेक्ट मथनीबेड़ा गांव को चयनित किया गया है और पहले चरण में 07 महिला हितग्राहियों का चयन किया गया है और जल्द ही गांव के अन्य हितग्राहियों को भी आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम को जिला पंचायत सदस्य नंदलाल राठौर सहित अन्य जनप्रतिनधियों ने भी संबोधित करते हुए इस पहल को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रामदई नाग, दीपेश अरोरा, प्रेम सिंह नाग सहित जनपद पंचाय सीईओ उत्तम महोबिया एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

यह परियोजना एक त्रिपक्षीय मॉडल पर आधारित है, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा मार्गदर्शन एवं निगरानी, महिला लाभाथिर्यो द्वारा संचालन एवं प्रबंधन तथा एबिस फूड एंड प्रोटीन्स द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट, तकनीकी सहयोग एवं बाजार उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अस्मिता परियोजना के अंतर्गत महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, वैज्ञानिक प्रबंधन एवं निरंतर फील्ड सपोर्ट प्रदान किया जाएगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि एवं जोखिम में कमी सुनिश्चित हो सके। इस मॉडल से महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। परियोजना के तहत प्रति महिला लाभार्थी को वार्षिक लगभग 1.5 लाख रुपये तक की शुद्ध आय का लक्ष्य रखा गया है, वहीं मासिक औसत आय 12 से 13 हजार रुपये तक होने की संभावना है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर पोषण सुधार एवं प्रोटीन उपलब्धता बढ़ाने में भी यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा भविष्य में सुकर पालन और मछली पालन को भी शामिल किया जाएगा।

परशुराम जयंती समारोह में पहुंचे उद्योग मंत्री व महापौर, दी अनेक सौगातें

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

प्रदेश के उद्योग, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन एवं महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत आज कोरबा में परशुराम द्विज परिवार व सर्वब्राम्हण समाज द्वारा आयोजित भगवान परशुराम जयंती समारोह में पहुंचे, दोनों समाज के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया तथा समाज के लोगों की मांग पर अनेकों सौगात प्रदान की, उन्होने भगवान परशुराम जी की जयंती की अपनी हार्दिक शुभकामनायें व बधाई समाज के लोगों को दी तथा उनके आशीर्वाद की कामना की। इस मौके पर सभापति नूतन सिंह ठाकुर व पार्षद नरेन्द्र देवांगन सहित जनप्रतिनिधिगण व समाज के लोग उपस्थित थे।

परशुराम जयंती के अवसर पर परशुराम द्विज परिवार व सर्वब्राम्हण समाज कोरबा के द्वारा अपने-अपने भवनों में परशमुराम जयंती समारोह का आयोजन किया गया। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन व महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने समारोह में पहुंचकर भगवान श्री परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा इस मौके पर अनेक सौगातें भी प्रदान की। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के द्वारा परशुराम द्विज परिवार के भवन के प्रथम तल के शेष कार्य एवं द्वितीय तल के निर्माण कार्य हेतु 25 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी, उक्त निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसका लोकार्पण आज उनके करकमलों से किया गया। इसी प्रकार सर्वब्राम्हण समाज के ब्रम्हवाटिका के समीप उद्योग मंत्री श्री देवांगन के प्रयास से जिला खनिज न्यास मद से 20 लाख रूपये की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण, प्रसाधन निर्माण व अन्य विकास कार्य कराये गये हैं, इसका लोकार्पण भी उद्योग मंत्री श्री देवांगन एवं महापौर श्रीमती राजपूत के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने भगवान परशुराम जी की जयंती की बधाई देते हुये कहा कि ब्राम्हण समाज हर वर्ग व समाज के कल्याण के लिये कार्य करता है, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा विश्व कल्याण की कामना रखता है। भगवान परशुराम का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, मैं यह कामना करता हूँ।

सभी समाज की चिंता करते हैं

महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने परशुराम जयंती की अपनी हार्दिक शुभकामनायें उपस्थित लोगों को दी तथा कहा कि मुझे खुशी है कि समाज के जो भवनों को समाज की सेवा में आज समर्पित किया जा रहा है, उन्होने कहा कि उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन सभी समाज व वर्ग के लोगों के हितों की चिंता करते हैं, सभी के लिये कार्य कर रहे हैं, आज कोरबा की जो व्यवस्थायें सुधर रही हैं, कोरबा विकास पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, सड़कों पर व्यवसाय करने वालों के लिये स्थाई व्यवस्था हो रही है, वह सब श्री देवांगन के आशीर्वाद व सहयोग से ही संभव हो पा रहा है।

इस अवसर पर सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि उद्योग मंत्री श्री देवांगन व महापौर श्रीमती राजपूत की यह जोड़ी कोरबा के विकास के लिये, नागरिक सुविधाओं की बेहतरी के लिये, पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है, इसी का परिणाम है कि कोरबा का तेजी से विकास हो रहा है, सभापति श्री ठाकुर ने इस मौके पर भगवान परशुराम जी की जयंती की अपनी हार्दिक शुभकामनायें दी।

इस अवसर पर वरिष्ठ नेता देवेन्द्र पाण्डेय ने कहा कि उद्योग मंत्री श्री देवांगन अपने सहज, सरल स्वभाव के लिये जाने जाते हैं, श्री देवांगन ब्राम्हण समाज ही नहीं बल्कि सभी समाज के लोगों का भरपूर सम्मान करते हैं, यही कारण है कि उन्हें सभी समाजों का पूरा आशीर्वाद भी मिल रहा है। वहीं वरिष्ठ नेता हरीश परसाई ने अपने उद्बोधन में कहा कि उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने हर समाज को सदैव कुछ न कुछ दिया है, वे आगे भी देते रहेंगे, महापौर श्रीमती राजपूत भी लोगों की भलाई के लिये, सदैव तत्पर रहती हैं, दोनों के प्रयास से कोरबा का तेजी से विकास होगा, मैं यह आशा करता हूँ। उन्होने कहा कि ब्राम्हण समाज सभी के लोगों की भलाई व सुख समृद्धि की सदैव कामना करता है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने घंटाघर में भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापना एवं चौक का नाम भगवान परशुराम चौक किये जाने का आग्रह उद्योग मंत्री व महापौर से किया।

इस मौके पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने दोनों भवनों के लोकार्पण के साथ-साथ अनेक सौगातें भी समाज के लोगों को दी। उन्होने परशुराम द्विज परिवार के भवन एवं सर्वब्राम्हण समाज के भवन में आवश्यकतानुसार संख्या में ए.सी. लगाये जाने की घोषणा की, इसी प्रकार परशुराम द्विज परिवार की महिला विंग की पदाधिकारियों द्वारा अपने सामाजिक कार्यक्रम हेतु 50 हजार रूपये की मांग किये जाने पर 01 लाख रूपये दिये जाने की घोषणा उद्योग मंत्री ने की। सर्वब्राम्हण समाज के भवन में आवश्यकता को देखते हुये बिना मांगे ही उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने 05 नग नये ए.सी. लगवाये जाने की घोषणा की। इसी प्रकार महिला विंग के सामाजिक कार्यक्रमों के लिये भी आर्थिक सहयोग प्रदान करने की घोषणा भी की।

उक्त दोनों कार्यक्रमों के दौरान चन्द्रलोक सिंह, सत्येन्द्र दुबे, राकेश वर्मा, मण्डल अध्यक्ष राजेश राठौर, प्रफुल्ल तिवारी, राजेन्द्र पाण्डेय, देवेन्द्र पाण्डेय, दुष्यंत तिवारी, हरीश परसाई, हेमंत शर्मा, डॉ.संजय तिवारी, अरूण शर्मा, अजय पाण्डेय, अधिवक्ता बृजेश शुक्ला, भूषण प्रसाद तिवारी, कमलेश मिश्रा, वाई.के.तिवारी, विकास जोशी, पुरूषोत्तम तिवारी, तपन तिवारी, जे.एन.दुबे, रश्मि शर्मा, शोभना परसाई, रेखा त्रिपाठी, गायत्री नायक, सुधा झा, राकेश मिश्रा, श्रीधर द्विवेदी, पुनीराम साहू, रामकुमार जोशी, ए.के.सतपठी, के.डी.दीवान, आशीष द्विवेदी, कृष्णा द्विवेदी, राजेश मिश्रा मिटठू, दिलीप पाण्डेय, कल्पना पाण्डेय, सावित्री शुक्ला, पुष्पा तिवारी, भारती पाण्डेय, दिलीप पाण्डेय आदि के साथ समाज के लोग उपस्थित थे।

सोलह दूनी आठ
नई दृष्टिबिंदु

साप्ताहिक कॉलम

याज्ञवल्क्य मिश्रा

साहब परेशान

एक वर्दीवाले साहब हैं। किसी दुश्मन ने खाता बही के साथ शिकायत चेंप दी कि साहब ने कई गुना संपत्ति ठोक ली है।साहब यूँ भी गरीबी से हर क्षण लड़ने वाली प्रजाति के हैं। साहब ने लिख कर दे दिया कि फलाँ खेत जमीन तो दहेज में मिला था। लेकिन मसला तब गंगा समझ के नाले में कूदने वाला हो गया जब उन्हे बताया गया कि लोकसेवक दहेज को यूँ लिखित में स्वीकारेगा तो बीएनएस की धारा लपटाएगी। साहब ने फौरन से पेश्तर नया लिखित जवाब दिया कि वो जो संपत्तियां हैं वो दान में मिली थी। इस पर फिर सवाल खड़ा हो गया है। साहब को कहा गया है कि दान में मिली अचल संपत्ति जिसकी क़ीमत सौ रुपये से ज़्यादा है उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए जिसपर दान का उल्लेख हो। वह रजिस्ट्री लाइए। अब साहब परेशान हलाकान हैं।दान वाली रजिस्ट्री कहां से आए। तिस पर मसला ये भी है कि उसी अचल सम्पत्ति पर पहले दहेज में मिला और फिर दान में मिला, ये बताने वाले दोनों ही काग़ज फाईल में जमा हैं। साहब आप कोई एक तो फड़वा लेते।

मिनिस्टर सर

अफवाहबाजों की पुड़िया भी गजब की होती है। अब देखिए एक मंत्रीजी को लेकर कैसी बातें उड़ा रहे हैं। मंत्रीजी के विभाग का कोई काम था,मिनिस्टर सर चाहते थे कि काम उनके घुंघरु को मिले। लेकिन नियम के फेर में काम सरकारी एजेंसी या कि ढवउ फेर के हाथ चढ़ गया। अफवाहबाजों का कहना ये है कि मिनिस्टर सर इस बात पर कुपित हैं और खुद ही मीडिया वीरों को संदेश भिजवा रहे हैं कि देखो जरा चादर फाड़कर,टेस्ट कराकर काम की क्वालिटी पर खबर छापिए। अपने राम का मानना है कि यह सारी बात झूठ है। मिनिस्टर सर ऐसा करा ही नहीं सकते। हाँ अब प्रेस की आजादी और निर्भीक रिपोर्टिंग के प्रशंसक हैं तो ये बोले होंगे कि, हमने तो बढ़िया काम हो इसके लिए प्लान दिया अब गड़बड़ी हो तो बताइएगा ताकि जनता को राहत मिले। दुश्मन इसी अच्छी बात को लाईस बाईस कर उड़ा रहे हैं।

किसकी मानें

स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट में पुलिस वाले अजीबो गरीब स्थिति में जा फंसे हैं। मसला ये है कि कप्तान यूँ तो ट्रेनिंग में हैं और सरकार ने वहां प्रभारी के रुप नए अफसर की तैनाती की है। लेकिन कप्तान ट्रेनिंग में रहते हुए भी व्हाट्सएप पर जानकारी ले रहे हैं और निर्देश भी दे रहे हैं। टी आई से लेकर सिपाही परेशान हैं कि मानना किसकी है। सरकार ने जिसे फिलहाल प्रभारी बनाया है उनकी या ट्रेनिंग पर गए कप्तान की।

साहब की अप्रसन्नता

एक रेंज के सबसे बड़े साहब बिल्कुल सुशासन सरकार की ही तरह हैं। जब न तब दिल लूट ले जाते हैं। अब बंगले के पेड़ों को काटना तो मसला पुराना है। अब सनातन धर्म संस्कृति में परम पूज्य बेल पीपल का पेड़ हो तो हो, जाने कितने कट गए। मसला अब उससे आगे का है। अबकि साहब ने रेंज के कई साहबों को नोटिस जारी कर सबको अप्रसन्नता का प्रमाण पत्र दे दिया है। वजह भी इतनी हल्की है कि जानकार सर धून लें।पुलिस में सब कुछ किताबों के आधार पर नहीं चलता कुछ व्यवहारिक भी चलता है। साहब ये मानते हैं कि व्यवहारिक कुछ नहीं होता। हर एफआईआर शिकायत पर थाना प्रभारी की मौजूदगी जरुरी है और उस पर मुकम्मल निगरानी के लिए उपर वाले अफसर हैं। आप छुट्टी गए हों या कहीं लॉ एंड ऑर्डर में। साहब को वही चाहिए जो कि किताब में है। किसी जलनखोर ने कहा है यूँ तो साहब भले आदमी हैं लेकिन पवित्र पेड़ों की जड़ समेत कटाई से जो पाप हो गया है वह पाप बुद्धि भ्रमित कर रहा है। साहब को शांति और पाप विमोचन मंत्र का पाठ करना चाहिए।

साहब अपने मिसरी हैं

कमिश्नरी वाले साहब की एक क्वालिटी ऐसी है कि मुरीद लोगों ने उन्हे मिसरी भईया का टाइटल दे दिया है। इस मामले में इतने प्रवीण हैं कि यदि एक्टिंग हो भी तो दिखती नहीं। वे मुकम्मल जानते हैं कि कमिश्नरी में जो अफसर आ रहे हैं उनसे ज्यादा यहां से भागने की तमन्ना रखने वालों की संख्या है। मानव संसाधन से समेत कई मसले हैं जिनसे कमिश्नरी जूझ रही है। लेकिन मिसरी भईया का जादू देखिए। मिसरी भईया जब मीटिंग लेते हैं तो उपस्थित अफसरों को यह लाईन जरुर बोलते है –ह्लआप लोग वो हैं जिन्हें चुन चुन कर यहां लाया गया है।आप लोग काबिल हैं इसलिए यहां है।ह्व मिसरी भईया इस बात को इतना मीठा बोलते हैं कि बैठक के हर अफसर को भीतर तक यक़ीं हो जाता है कि जो बात कही गई है वही सही है और अंतिम रुप से सही है। यह यक़ीं ऐसा होता है कि संसाधनों से लेकर कोई अन्य मसला हो कोई चूँ से चां नहीं करता। क्योंकि मिसरी भईया की मीठी बातों का नशा ही ऐसा होता है।

देन व्हाई वाज दिस डन

सुशासन सरकार के फैसले का जिक्र ना हो तो सहाफी के भीतर मौजूद सरकार का भगत मानेगा कहाँ। अब देखिए सुशासन बाबू से लेकर केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने एलान कर दिया कि तीस मार्च को नक्सलवाद समाप्त हो चुका। पर सुशासन सरकार ने इस एलान के बावजूद कमिश्नरी समेत अन्य जगहों से दरोगा साहब लोग को जंगलवार ट्रेनिंग रवानगी दे दी गई है। जंगलवार ट्रेनिंग क्यों हो रही थी क्योंकि माओवाद से गुरिल्ला वार लड़ना था।जब माओवादी है हीं नहीं जैसा कि राज्य और केंद्र की सरकार कह चुकी है तो काहे भेजे भैया। लेकिन जैसा कि सहाफी कहता है तो उसे फिर दोहराता है जो समझ ना आए उसे ही सुशासन माना जाना चाहिए। और सरकार सर्वप्रभुता संपन्न होती है जो करती है सो सही करती है और अपन सच्चे नागरिक की तरह सरकार के साथ हैं। बाकी हर सवाल बेफजूल है।

MLA मैडम का घड़ी बंद!

सूबे में एक जगह बीजेपी की विधायक मैडम विकट जोर से इलाके के एसडीएम पर बिदक गईं। इस कदर नाराज हुईं कि कलेक्टर को फोन लगाकर बोल गईं कि, चौबीस घंटे में एसडीएम नहीं हटा तो कार्यकर्ताओं समेत धरना दे दूँगी। अब विधायक मैडम के इस अल्टीमेटम को 48 घंटे बीत चुके है। ना एसडीएम हटे हैं ना धरना प्रदर्शन हुआ है। सहाफी को बताया गया है कि, यहां सांसद से लेकर मैडम विधायक सहित शेष विधायक भी बीजेपी के हैं। पर मैडम पड़ जाती है अकेले, क्योंकि सांसद जी से सहमति लिए बगैर कुछ होता नहीं। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेसी मौज लेते हुए कह रहे हैं – पत्रकार जी, धरना तो होकर रहेगा बस अभी विधायक मैडम जी का घड़ी बंद हो गया है। घड़ी चालू होगी तब तो चौबीस घंटा तय होगा।

ये किस रेंज का किस्सा है

एक रेंज में कुछ अजब गजब सा हो रहा है। जाने दुश्मनों की उड़ाई अफवाह है या कुछ और बात है। पर जो भी है वो यह है कि,साहब हड़प्पा कालीन विभागीय जांच की नस्तीबद्ध फाईलों को खोज कर उन पर नोटिस जारी कर दे रहे हैं। हालाँकि नोटिस के आगे कुछ और हो नहीं रहा है।दुश्मनो की उड़ाई अफवाह है कि, यह मसला भेंट मुलाक़ात के बाद सलट जाता है। अपने राम का मानना है कि यह बात सिरे से ग़लत है। क्योंकि इस सहाफी को याद है कि एक किसी दूर रेंज में एक साहब पहुंचे थे। नौकरी से हटाए जाने के बाद वापसी हुई थी। उन्होंने बिल्कुल यही पैटर्न अपनाया था। महके बुरी तरह और जब रिटायर हुए तो महकमे ने जश्न मनाया था। अपने को यक़ीं है ये रेंज वाले साहब इस क़िस्से को जानते होंगे।

चुगली वाला चेंबर

पुलिस महकमे के सबसे बड़े कार्यालय में एक चैंबर इन दिनों अपेक्षाकृत सूना है। यह चैंबर ह्लआ बहन चुग़ली करेंह्व के कारण चर्चा के केंद्र में रहता है।अफवाहें कहती हैं कि जितना लाईस बाईस अंधेर सटकी तीन तूफानी बग़ैर सिर पैर के छपता और वितरित होता है, उसका उद्भव इसी चैंबर से होता है। इस चैंबर के दो हीरे हैं एक तो वे हैं जिनका ये चैंबर है और दूसरे वो साहब के खास मित्र हैं जो डायरी में तिलिस्मी कहानियाँ लिखने के लिए जाने जाते हैं। मगर फि लहाल ये चैंबर सूना है। पता नहीं बात क्या हो गई है।

रिनुअल चार्ज

सुशासन सरकार को अपने उन कमर्चारियों की ढंग से पता तलाश कर रेवेन्यू जनरेट और रिकवरी के काम में लगाना चाहिए जो रेत से भी तेल निकालने में सिद्ध हैं। सरकार पता नहीं क्यों इन की कदर नहीं करती।एक इंडस्ट्रियल जिला है। अब इंडस्ट्री है तो लेबर भी हैं, टार्गेट और प्रोडक्शन को लेकर तनावग्रस्त कंपनियों के साहब भी हैं। चुंकि इनकी संख्या ज्यादा है तो इनके लिए इस इलाके में बार भी ठीक ठाक आँकड़े में है।चुंकि बार है रिनुअल भी होता है, उसकी फीस पटती है। इस जिले को लेकर अफवाह का धुआँ उड़ रहा है कि,रिनुअल चार्ज के साथ हैंडसम अमाउंट को रिचार्ज के रुप में लिया गया है। सच झूठ तो विभाग जाने या बार वाले जानें।

वाह री कांग्रेस

सक्ती पॉवर प्लांट मामले में काँग्रेस ने विकट तीन तूफान मचाया है। पीसीसी चीफ बैज हों या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत। बबलू भैया तो खैर बालको चिमनी कांड को भी याद कर के दहकता बयान जारी किए। लेकिन इस मामले को ध्यान से मगर दूर से देख रहे कुछ विद्वानों का मानना है कि कांग्रेस ने इस मामले में छत्तीसगढ़ में जो किया है उसका सही सटीक पता राहुल गांधी को चल जाए तो सबकी पेशी हो जाएगी। अफवाह बाज कहते हैं प्लांट संचालक तो सेमी गव्हर्मेंट एजेंसी थी।मजदूरों को लाने वाली ठेका कंपनी थी।लेकिन जिन्हे आरोपी बनाया गया उनमें ये लोग थे ही नहीं, और जो आरोपी बनाए गए उनका मामला वैसा ही था जैसे कहीं छुरा कट्टा चल जाए और एफआईआर में मुख्यमंत्री गृहमंत्री का नाम डाल दिया जाए। अफवाहों की उड़ान कहती है कि,एफआईआर में दर्ज नाम के प्रायोजक वही हैं जिनसे कोर्ट में वेदांता कंपनी का मुक़दमा चल रहा है। पर कांग्रेसी भोले हैं उन्हें पता थोड़ी होगा ऐसा कुछ मसला।

भोले कांग्रेसी

सक्ती पॉवर प्लांट मामले में काँग्रेस ने विकट तीन तूफान मचाया है। पीसीसी चीफ बैज हों या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत। बबलू भैया तो खैर बालको चिमनी कांड को भी याद कर के दहकता बयान जारी किए। लेकिन इस मामले को ध्यान से मगर दूर से देख रहे कुछ विद्वानों का मानना है कि कांग्रेस ने इस मामले में छत्तीसगढ़ में जो किया है उसका सही सटीक पता राहुल गांधी को चल जाए तो सबकी पेशी हो जाएगी। अफवाह बाज कहते हैं प्लांट संचालक तो सेमी गव्हर्मेंट एजेंसी थी।मजदूरों को लाने वाली ठेका कंपनी थी।लेकिन जिन्हे आरोपी बनाया गया उनमें ये लोग थे ही नहीं, और जो आरोपी बनाए गए उनका मामला वैसा ही था जैसे कहीं छुरा कट्टा चल जाए और एफआईआर में मुख्यमंत्री गृहमंत्री का नाम डाल दिया जाए। अफवाहों की उड़ान कहती है कि,एफआईआर में दर्ज नाम के प्रायोजक वही हैं जिनसे कोर्ट में वेदांता कंपनी का मुक़दमा चल रहा है। पर कांग्रेसी भोले हैं उन्हें पता थोड़ी होगा ऐसा कुछ मसला।अब हर बात जो राहुल को और दुनिया को पता चले वो छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी भी जानें ये जरुरी थोड़ी है।

ई-रिक्शा पर 'परमिट राज' के संकट

क्या गरीब चालकों को एजेंटों के चंगुल में फंसाने की रची जा रही साजिश

नरेन्द्र डाकलिया / रायपुर

छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग की एक कथित 'कुदृष्टि' ने प्रदेश भर में हजारों ई-रिक्शा चालकों की नींद उड़ाने की साजिश रची जाने का खुलासा हुआ है। आम आदमी की लाइफलाइन बने ई-रिक्शा को अब प्रशासनिक तंत्र के एक ऐसे 'मकड़जाल' में फंसाने की तैयारी है, जो सीधे तौर पर गरीब मेहनतकशों को आरटीओ दलालों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देगा।

नियमों के नाम पर 'शोषण' की तैयारी

परिवहन विभाग द्वारा ई-रिक्शा के लिए परमिट प्रणाली, फिटनेस और सालाना भारी-भरकम शुल्कों को अनिवार्य करने की सुगबुगाहट दिखलाई देना शुरू हो गई है। जानकारों का कहना है कि यह कदम जनहित में नहीं, बल्कि दलालों की कमाई का जरिया बनाने के लिए उठाया जा सकता है।

ई-रिक्शा चालक जो पहले से ही अपने ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक लोन की किस्तों और परिवार का पेट पालने की जद्दोजहद में जुटे हैं, उन पर अब 'परमिट' और 'फिटनेस' की तलवार लटकाने कि साजिश रची जा रही है। आरोप है कि यह नियम केवल एक बहाना है ताकि ई-रिक्शा चालकों को दफ्तरों के चक्कर कटवाकर आरटीओ एजेंटों के पास जाने के लिए मजबूर किया जा सके, जहाँ से वसूली का नया दौर शुरू होगा।

क्यों निशाने पर है ई-रिक्शा?

ई-रिक्शा ने शहर की यातायात व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया है। जहाँ ऑटो-रिक्शा चालक मनमाना किराया (50 से 100 रुपये) वसूलने के लिए बदनाम हैं, वहीं ई-रिक्शा केवल 10 रुपये में आम जनता को सुलभ सफर दे रहे हैं। इस लोकप्रियता से जहां एक ओर आम आदमी खुश है, वहीं परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों और ऑटो माफियाओं को यह नागवार गुजर रहा है। अब फिटनेस और परमिट का जाल बुनकर उन ई-रिक्शा को रास्ते से हटाने या उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा 'टेक्स' और 'एजेंट कमीशन' के नाम पर डकारने की सुनियोजित कोशिश दिखाई दे रही है।

चालको का दर्द: "हम लुटेरों के हाथ लग जाएंगे"

कई ई-रिक्शा चालको ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "हम पहले ही अपना लाइसेंस बनवाकर, बैंक का कर्जा लेकर गाड़ी चला रहे हैं। अब हमसे और परमिट और फिटनेस की मांग करना हमें पूरी तरह बर्बाद कर देगा। हमें पता है कि जब यह नियम लागू होंगे, तो सरकारी दफ्तर के बाहर बैठे दलाल हमसे मोटी रकम वसूलेंगे।"

सवाल जो सिस्टम पर उठ रहे हैं

जब ई-रिक्शा चालक पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस और टैक्स जमा कर रहे हैं, तो परमिट और फिटनेस का नया बोझ किस आधार पर थोपा जा सकता है। क्या परिवहन विभाग का असली मकसद सड़क सुरक्षा है या फिर आरटीओ दलालों के लिए नई कमाई की राह खोलना। जो परिवहन व्यवस्था आम जनता को 10 रुपये में राहत दे रही है, उसे 'अराजक' बताकर उसे खत्म करने की साजिश क्यों रची जा रही है।

यदि शासन-प्रशासन ने बिना किसी व्यावहारिक अध्ययन के ये नए नियम लागू किए, तो हजारों ई-रिक्शा चालक बेरोजगार हो जाएंगे और आम जनता पर एक बार फिर से 'ऑटो माफिया' का दबाव बढ़ जाएगा। यह समय गरीब मेहनतकशों पर शिकंजा कसने का नहीं, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करने का है। क्या आपको लगता है कि ई-रिक्शा पर नए नियम लगाना, गरीबों का शोषण है? हमें अपनी राय साझा करें।

अवैध संबंधों के संदेह में युवक पर किया प्राणघातक जानलेवा हमला, गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

अवैध संबंधों के संदेह और आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में दुर्ग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार भी जप्त किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 19 अप्रैल 2026 को प्रार्थी परदेशी राम निर्मलकर (55 वर्ष), निवासी नयापारा दुर्ग ने थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पुत्र हेमंत निर्मलकर पर 18 अप्रैल की रात करीब 10 बजे उतई तिराहा स्थित टेम्पो स्टैंड के पास आरोपी ने जान से मारने की नीयत से हमला किया।

रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी अंकित सिन्हा को अपनी पत्नी के संबंधों को लेकर संदेह था, जिसके चलते वह हेमंत निर्मलकर से रंजिश रखता था। इसी विवाद के चलते आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए शंकरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 198/2026 धारा 109 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान आरोपी अंकित सिन्हा (28 वर्ष), निवासी ग्राम बोरतरा थाना गुरूर जिला बालोद, हाल निवासी मांढर जिला रायपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इस कार्रवाई में थाना सिटी कोतवाली के निरीक्षक नवीन कुमार राजपूत, प्रधान आरक्षक राकेश निर्मलकर सहित पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।

भाजपा नेता कन्हैया सोनी की बड़ी पहल

छत्तीसगढ़ से बस द्वारा कोलकाता रवाना हुए सैकड़ों स्वणर्कार कारीगर, करेंगे भाजपा के पक्ष में मतदान

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भाई कन्हैया सोनी ने संगठन के प्रति अपनी अटूट निष्ठा और चुनावी सक्रियता का परिचय देते हुए एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया। उन्होंने अपने भिलाई दुर्ग में कार्यरत स्वणर्कार समाज के कारीगरों और उनके परिवारों को मतदान हेतु प्रेरित किया है।

कन्हैया सोनी ने विशेष बसों का प्रबंध कर इन मतदाताओं को उनके मूल निवास कोलकाता भेजने की व्यवस्था की है। ओर स्वयं भी कोलकाता गए व रवाना होने से पूर्व कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक 'जय श्री राम' और 'भाजपा जिंदाबाद' के नारे लगाए। श्री सोनी ने कहा कि, "राष्ट्रहित में प्रत्येक वोट कीमती है। हमारे स्वणर्कार भाई-बहन कोलकाता जाकर भाजपा के पक्ष में मतदान कर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।" इस पहल की राजनीतिक गलियारों में जमकर सराहना हो रही है।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100